



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2013/ आषाढ़ 5, 1935

No. 140]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2013/ASHADHA 5, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2013

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम परक्लोरेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।
फा. सं 14/10/2012-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और उसके अंतर्गत बने, समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1975 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) को कैलिबर कैमिकल्स प्रा. लिमिटेड से चीन जन गण. (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम परक्लोरेट के कथित पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आरोप लगाते हुए तथा पाटनरोधी जांच शुरू करने एवं पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध करते हुए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत एक लिखित आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है।
- आवेदनपत्र की प्रारंभिक जांच में कुछ कमियां पाई गईं जिनमें आवेदक ने बाद में सुधार कर दिया। अतः यह माना गया कि आवेदनपत्र सभी प्रलेखनों से युक्त है। प्राधिकारी ने, आवेदन द्वारा जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के आधार पर सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में जांच प्रारंभ करने का निश्चय किया।
- प्राधिकारी ने, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच प्रारंभ करने से पहले, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली कथित क्षति का आरोप लगाते हुए आवेदन प्राप्त होने की सूचना सम्बद्ध देश के भारत स्थित राजदूतावास को अधिसूचित कर दी।
- तदनुसार, प्राधिकारी ने कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी डिग्री तथा प्रभावों का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी उपाय की राशि, जो यदि उद्ग्रहित की गई होती तो घरेलू उद्योग की होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होती, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुरूप कथित पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के संबंध में जांच प्रारंभ की।

क. प्रक्रिया

6. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया:

- i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप-नियम 5 (5) के अनुसार जांच प्रारंभ करने की प्रक्रिया से पहले पाटन के आवेदनपत्र की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास को सूचना भेजी।
- ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हुए दिनांक 27 जून, 2012 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।
- iii. प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनका विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था) तथा उद्योग एसोसिएशनों को भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया।
- iv. प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों (जिनका विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था) को अग्रेषित की और उन्हें सुझाव दिया कि वे इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करें।
- v. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार सभी ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के भारत स्थित राजदूतावास को उपलब्ध कराई। आवेदन की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जहां इसके लिए अनुरोध किया गया, भी प्रदान कराई गई।
- vi. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार प्रश्नावलियां भेजी:

- क. डालियान गौजिया कैमिकल कम्पनी, लिमिटेड
- ख. डालियान टाउवी इंटरनेशनल टैंड कम्पनी, लिमिटेड
- ग. चांगसा झियांग वेई कैमिकल टैंड कम्पनी, लिमिटेड
- घ. डालियान बाओबू कामर्शियल बिजनेस कम्पनी लिमिटेड
- ड. तियान्जिन बैरन इंटरनेशनल टैंड कम्पनी लिमिटेड
- च. छानसा जियांग वेई कैमिकल टैंड कम्पनी लिमिटेड

vii. संबद्ध देश से किसी भी निर्यातक ने इस अधिसूचना की शुरुआत के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तथापि, मैसर्स डालियान क्लोरेट लिमिटेड, नामक एक निर्यातक से एक प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। जिसने अपना प्रत्युत्तर जांच शुरुआत अधिसूचना के काफी समय बाद प्रस्तुत किया फिर भी प्राधिकारी ने यह प्रत्युत्तर स्वीकार कर लिया। इस उत्पादक एवं निर्यातक के प्रत्युत्तर की जांच करने पर यह प्रदर्शित हुआ कि यह प्रत्युत्तर पर्याप्त नहीं है और तदनुसार उत्पादक निर्यातक को एक त्रुटि पत्र लिखा गया जिससे कि वह उसका उत्तर दे सके। चूंकि निर्यातक ने त्रुटि पत्र का प्रत्युत्तर निर्यात प्रश्नावली के स्वरूप और ढंग में प्रस्तुत नहीं किया इसलिए प्राधिकारी ने उसे स्वीकार नहीं किया।

viii. संबद्ध वस्तु के भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की मांग करते हुए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अंतर्गत प्रश्नावलियां भेजी गईं:

- क. इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड
- ख. सालर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ग. सुमा कैमिकल्स प्रा. लिमिटेड

ix. जांच शुरूआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने प्रत्युत्तर दिया

- क. सुमा कैमिकल्स प्रा. लिमिटेड
- ख. इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड
- ग. सालर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

x. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया।

xi. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से, जांच की अवधि सहित, विगत तीन वर्षों में सम्बद्ध वस्तु के आयातों का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम में डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त संव्यवहार-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। डीजीसी आई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए संव्यवहारवार आंकड़ों में कुछ त्रुटियां थीं और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखते हुए इन त्रुटियों में उपयुक्त सुधार किया गया।

xii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर आधारित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बिक्री करने की इष्टतम लागत का निर्धारण किया गया ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग के परिसरों का स्थल पर सत्यापन करके किया गया।

xiii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के विचार मौखिक रूप से जानने के लिए दिनांक 01.05.2013 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया। सुनवाई के दौरान उपस्थित हितबद्ध पक्षकारों से कहा गया कि वे सुनवाई में अभिव्यक्त किए गए मौखिक विचारों को लिखित रूप में दर्ज करें और उन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त विचारों की प्रत्युक्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतिकरणों और उनकी प्रत्युक्तियों पर संगत समझी गयी सीमा तक विचार किया गया।

xiv. आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों का जरूरी समझी गई सीमा तक स्थल पर जाकर सत्यापन किया गया।

xv. नियमावली के नियम 16 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया तथा उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है। निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं—

- क. इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड
- ख. सालर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ग. मै. कैलिवर कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

xvi. यह जांच 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ करके 31 मार्च, 2012 (जांच की अवधि) तक की अवधि के लिए किया गया। क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच अप्रैल, 2008 –मार्च, 2009, अप्रैल 2009–मार्च, 2010, अप्रैल 2010–मार्च, 2011, तक की अवधि और जांच की अवधि को शामिल किया गया है।

- xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक उस अंतिम जांच परिणाम में निराकरण कर दिया गया है।
- xviii. *** इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व है और उस पर प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत विचार किया गया है।
- xix. जांच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डालर=48.14/-रुपये है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घरेलू उद्योग के विचार

7. सोडियम परक्लोरेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक फार्मूला एन ए सी आई ओ है। यह वाणिज्यिक रूप से सोडियम परक्लोरेट (निर्जलीकृत) और सोडियम परक्लोरेट (मोनोहाइड्रेट) के रूप में उपलब्ध है। मोनोहाइड्रेट में पानी का एक अणु मौजूद होता है। यह सामान्य परक्लोरेट लवणों में सर्वाधिक घुलनशील है।
8. सोडियम परक्लोरेट एक सफेद क्रिस्टलाइन हाइड्रोस्कोपिक ठोस होता है जो जल और अलकोहल में अत्यधिक घुलनशील है। यह सामान्यतः मोनोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होता है जिसका रहस्यिक क्रिस्टल ढांचा होता है। इसका प्रयोग खनन कार्य के लिए विस्फोटकों का विनिर्माण करने, परक्लोरिक एसिड तथा अन्य परक्लोरेट विनिर्माण और इंजीनियरिंग प्लास्टिक के लिए यू वी स्टैबिलाइजर का विनिर्माण करने में किया जाता है। इसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 में उपशीर्षक 282990 और 28299010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु और सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय हैं।
10. प्रत्युत्तरदाता हितबद्ध पक्षकार ने स्वयं घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद का अंतरबदल करके प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त, आयातित उत्पाद तथा घरेलू उत्पाद दोनों ही सोडियम परक्लोरेट हैं। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु और चीन से आयातित वस्तु में कोई विशेष अंतर नहीं है।
11. यह प्रकल्पना करने का कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता निर्जलीकृत ग्रेड का उत्पादन नहीं करता है। वास्तव में तो याचिकाकर्ता निर्जलीकृत ग्रेड का उत्पादन और बिक्री दोनों कर रहा है।
12. घरेलू उद्योग के लिए पाटन एवं क्षति को एक 'वस्तु' के लिए देखा जाना अपेक्षित है न कि 'एक वस्तु के प्रत्येक प्रकार के लिए देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी उत्पाद प्रकार का अपवर्जन केवल तभी कर सकता है जब उस उत्पाद प्रकार अथवा उसके समान वस्तु को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत न किया जाता हो। निर्दिष्ट प्राधिकारी को भारत में आयात न किए जाने वाले उत्पाद प्रकार का अपवर्जन करने पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि भारत में आयात न किए उत्पाद प्रकार का अपवर्जन करने पर विचार करने के इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है तो व्यावहारिक रूप से इसका आशय 'वस्तु' की परिभाषा को कम करके 'उत्पाद प्रकार' के रूप में करनी चाहिए और विचाराधीन उत्पाद को केवल आयातित उत्पाद प्रकार के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।
13. यह तथ्य पूर्णतया निराधार है कि एक ग्रेड की कीमत दूसरे ग्रेड की कीमत से उच्चतर है। प्राधिकारी ने अब तक ऐसी कई जांच की है जहां एक ग्रेड की कीमत दूसरे ग्रेड की कीमत से अधिक है और उन पर एक वस्तु के रूप में विचार किया गया है जैसे कास्टिक सोडा-लाई और फ्लेक, फास्फोरिक एसिड-तकनीकी और खाद्य ग्रेड, एच आर क्वाइल्स-प्लेट्स एवं शीट्स। प्रकटन पश्चात घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरणों में यह दोहराया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सोडियम परक्लोरेट और सम्बद्ध देश से आयातित सोडियम परक्लोरेट में कोई

अंतर नहीं है और इस जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम परक्लोरेट है। प्राधिकारी के समक्ष किए गए प्रस्तुतिकरणों में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने निर्जलीकृत ग्रेड रूपों में भी सोडियम परक्लोरेट का विनिर्माण और उसकी बिक्री की है और इस संबंध में उन्होंने बीजकों की प्रतियां सलग्न की हैं जो सोडियम परक्लोरेट (निर्जलीकृत ग्रेड) की बिक्री दर्शाती हैं।

आयातकों/उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. आयातकों/उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं:

- क. आयातित और घरेलू उत्पाद को 'समान वस्तु' के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ख. निर्जलीकृत ग्रेड का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता उसकी निर्माण नहीं कर रहा है और इसका भारत में आयात नहीं हो रहा है। अतः घरेलू उद्योग को निर्जलीकृत ग्रेड के कारण कोई क्षति नहीं हो सकती है।
- ग. दोनों ग्रेडों के बीच भारी कीमत और लागत अंतर होने के कारण वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा का अभाव है। निर्जलीकृत ग्रेड की कीमत मोनोहाइड्रेट ग्रेड की कीमत की तुलना में कम से कम 25 प्रतिशत अधिक है।
- घ. प्रकटन पृष्ठ 11 में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने प्राधिकारी का ध्यान घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उस आयात सांख्यिकी की ओर आकृष्ट किया है जिसमें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निर्जलीकृत ग्रेड का विशेष रूप से अपवर्जन किया गया है। इस संबंध में उन्होंने विभिन्न प्रदर्श प्रदर्शित किए हैं जहां घरेलू उद्योग ने केवल मोनोहाइड्रेट ग्रेड अर्थात् याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में सलग्न आयात सांख्यिकी में विनिर्मित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत प्रपत्र-IV क और ख में ही उल्लेख किया है। उन्होंने पुनः यह उल्लेख किया है कि भारत को निर्जलीकृत ग्रेड का आयात नहीं किया जाता है और घरेलू उद्योग ने निर्जलीकृत ग्रेड के संबंध में कोई क्षति सूचना प्रदान नहीं की है।
- ड. आयातक द्वारा पुनः यह प्रस्तुत किया गया है कि जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र में ही निर्जलीकृत ग्रेड को शामिल नहीं किया गया है तो इसी ग्रेड का उत्तरवर्ती समावेशन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भारत में निर्जलीकृत ग्रेड का आयात नहीं किया जाता है और घरेलू उद्योग ने निर्जलीकृत ग्रेड के संबंध में कोई क्षति सूचना प्रदान नहीं की है। इसके अतिरिक्त आयातक द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वे निर्जलीकृत ग्रेड का उत्पादन और उसकी बिक्री करने में अंतर्ग्रस्त हैं फिर भी उन्होंने अन्य हितबद्ध पक्षकारों अथवा प्राधिकारी के समक्ष इस दावे को प्रमाण सहित सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और प्रस्तुतिकरण में केवल अभिकथन कर देना ही इस दावे को प्रमाण से सिद्ध करना ही पर्याप्त नहीं है। अतः उन्होंने प्राधिकारी से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निर्जलीकृत का अपवर्जन करने का अनुरोध किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

15. वर्तमान जांच के उद्देश्यों के लिए विचाराधीन उत्पाद चीन जन गण से आयातित "सोडियम परक्लोरेट" है। सोडियम परक्लोरेट का प्रमुख कार्य खनन के लिए विस्फोटकों का विनिर्माण, परक्लोरिक एसिड तथा अन्य परक्लोरेट्स विनिर्माण और इंजीनियरिंग प्लास्टिक के लिए यू वी स्टैबिलाइजर का विनिर्माण करना है। सोडियम परक्लोरेट एक कार्बनिक यौगिक है तथा इसे सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में अध्याय 28 के अंतर्गत (परक्लोरेट्स के अंदर 8 अंकीय उपशीर्षक 28299010 के अंतर्गत) वर्गीकृत किया गया है; तथापि यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सूक्ष्म है और यह वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

16. समान वस्तु के सम्बंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में प्रावधान है कि:
"समान वस्तु" का आशय ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटित की जा रही विचाराधीन वस्तु के समान या समरूप है अथवा उक्त वस्तु की अनुपस्थिति में, कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि पूरी तरह से समान न हो परंतु विचाराधीन वस्तु के कुछ गुणधर्मों को निकट से अभिव्यक्त करती हो।'
17. रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी का यह विचार है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु तथा सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु अपने गुणधर्मों खासकर आचरण, वास्तविक एवं रासायनिक गुणधर्मों विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यो एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण सभी के रूप में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों का प्रयोग अदल बदलकर कर रहे हैं।
18. इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बिना किसी समर्थकारी साक्ष्य के यह तर्क दिया है कि घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद के समान वस्तु नहीं है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के इस तर्क के संबंध में कि लागत और कीमत बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में उपलब्ध है, यह नोट किया जाता है कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं कराई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। वेब तलाश में भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऐसी कोई सूचना नहीं दर्शायी गई है। तथापि, याचिका में प्रदान कराई गई जानकारी यह दर्शाती है कि घरेलू और आयातित उत्पाद दोनों एक समान वस्तु हैं।
19. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि निर्जलीकृत ग्रेड का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता उसका विनिर्माण नहीं कर रहा है और इसका भारत में आयात नहीं किया जा रहा है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग निर्जलीकृत ग्रेड का विनिर्माण नहीं कर रहा है। प्रकटन पश्चात आयातक प्रस्तुतीकरण के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि याचिका में सोडियम परक्लोरेट के रूप में विचाराधीन उत्पाद का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आयातक द्वारा अपने प्रकटन पश्चात अभिकथन में उद्धृत और संलग्न किए गए कुछ प्रदर्शों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यद्यपि कुछ प्रदर्शों में उत्पाद शीर्षक का एस पी एम (सोडियम परक्लोरेट मोनोहाइड्रेट) के रूप में उल्लेख किया गया है फिर भी घरेलू उद्योग से प्राप्त उत्तरवर्ती क्षति सूचना में समग्र रूप से सोडियम परक्लोरेट के संबंध में सूचना को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, दर्शाये गए आंकड़ों के प्रदर्शों में से एक प्रदर्श में विचाराधीन उत्पाद के रूप में चीन जन.गण से आयातित सोडियम परक्लोरेट तथा सोडियम परक्लोरेट मोनोहाइड्रेट का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के लिए समस्त क्षति सूचना तथा गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण समग्र रूप से सोडियम परक्लोरेट के रूप में किया गया है। जैसा कि इस जांच-परिणाम में पहले ही अन्यत्र उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग ने सोडियम परक्लोरेट एनहाइड्रस ग्रेड को दर्शाते हुए भी बिक्री बीजक की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई सूचना से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग वास्तव में दोनों ग्रेडों अर्थात् मोनोहाइड्रेट्स तथा निर्जलीकृत ग्रेड का विनिर्माण करती है। इसलिए, इस ग्रेड का विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन करना वांछित नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। इस जांच में सोडियम परक्लोरेट के सभी रूपों को कवर किया गया है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

"घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु का विनिर्माण करने में अथवा उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में समग्र रूप से लगे घरेलू उत्पादकों अथवा उनसे है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक आउटपुट उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पाद का प्रमुख अनुपात बनता है, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जब ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के

निर्यातकों अथवा आयातकों से सम्बंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हों, ऐसे मामलों में वाक्यांश "घरेलू उद्योग" को शेष उत्पादकों का उल्लेख करते हुए, के रूप में माना जा सकता है।

21. इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड (आईईएल) के इस तर्क के सम्बंध में कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में निगमित एक कम्पनी है और नियमावली के नियम 2 (ख) के अंतर्गत यह घरेलू उद्योग बनती है। आई ई एल ने यह सिद्ध नहीं किया है कि किस तरह याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उत्पादक और घरेलू उद्योग नहीं बनते हैं।
22. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकार्ड की जांच करने के पश्चात यह नोट किया जाता है कि यह आवेदन मैसर्स कैलिबर कैमिकल्स प्रा. लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जो विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र विनिर्माता है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही इस विचाराधीन उत्पाद का भारत में कोई अन्य उत्पादक है। अतः प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन के प्रमुख अनुपात को कमांड करता है और नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनता है।

घ. गोपनीयता

घरेलू उद्योग के विचार

23. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है:
 - i. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। यह भी उल्लेख किया गया कि नियम-7 निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई सूचना नामंजूर करने की अनुमति नहीं देता है। सभी संगत जानकारी अपेक्षित सीमा तक उपलब्ध कराई गई है। आयातक जांच की प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है।
 - ii. याचिकाकर्ता ने उस सभी सूचना का प्रकटन किया है जो नियमों के अंतर्गत देना अपेक्षित था। याचिकाकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसलिए यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट का प्रकटन हितबद्ध पक्षकारों को करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने संपूर्ण क्षति अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट के उद्धरण उपलब्ध कराए हैं।
 - iii. निर्यात कीमत से कटौती का स्पष्टीकरण अगोपनीय पाठ के रूप में दिया गया है।

आयातकों/उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

24. गोपनीयता के संबंध में आयातकों/उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए:
 - i. याचिकाकर्ता द्वारा (क) सोडियम क्लोरेट के लिए विचार की गई कीमत का स्रोत (ख) क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा (ग) फैंक्टरी बाह्य कीमत पर पहुंचने के लिए निर्यात कीमत से कटौती के संबंध में अनावश्यक गोपनीयता का दावा किया गया है।

[illegible]

ड. विविध प्रस्तुतिकरण
घरेलू उद्योग के विचार

27. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं:
- विचाराधीन उत्पाद की लागत लेखा, सालर इण्डस्ट्री की लागत का एक छोटा सा हिस्सा बनता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क कम्पनी की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कोई महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी क्योंकि निर्यात के लिए आयातों की अनुमति पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना दी जाती है।
 - पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आयातों पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, परन्तु यह तो पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति का प्रशमन करने के लिए है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा को पुनर्स्थापित किया जा सके, जो कि सामान्यतः देश के हित में हो।
 - इस याचिका का उद्देश्य घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही पाटन की स्थिति का निराकरण करना है। इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य नहीं है।
 - याचिकाकर्ता ने आयात आंकड़ों के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी प्रदान कराई है। यह सूचना पाटनरोधी विधि तथा व्यवहार के आशय के अंतर्गत सकारात्मक साक्ष्य बनती है। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस उद्देश्य के लिए द्वितीयक स्रोत से आंकड़ों को पद्धतिक्रम रूप से स्वीकार किया है।
 - यह याचिका मै. बालाजी डाटा इन्फार्मेशन सर्विसेस से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित थी और इस याचिका के जरिए इसके अगोपनीय पाठ का सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन किया गया है।

आयातकों/उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

28. आयातकों/उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विविध प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं:-
- यह याचिका घरेलू विनिर्माताओं द्वारा आयातित उत्पाद की सेवा सहित बेहतर गुणवत्ता और कीमत तक पहुंच को विकृत करके संकुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संधियों की भावनाओं के प्रतिकूल है।
 - वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए सालर इंडस्ट्रीज को अपनी लागत न्यूनतम संभावित स्तर तक बनाए रखनी पड़ी। कच्चे माल का आयात कार्यनीति का भाग है जिससे कि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। एकमात्र उत्पादक की ओर से, जो तब एकाधिकार स्थापित कर लेगा, अतिरिक्त शुल्क का अधिरोपण करना आयातकों के हित के विपरीत है।
 - लेनदेनवार आयात सांख्यिकी का प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया। घरेलू उद्योग को सार्वजनिक सुनवाई के समय आयात सांख्यिकी के आधार में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संशोधित आंकड़े विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

- iv. यदि प्राधिकारी इस आयात सांख्यिकी पर विचार करने पर निर्णय लेते हैं तो हितबद्ध पक्षकारों को डीजीसीआईएस आंकड़े तथा याचिकाकर्ता द्वारा इन आयात आंकड़ों पर पहुंचने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति का विस्तृत विवरण प्रदान कराया जाना चाहिए।
- v. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को डीजीसीआईएस एंड एस तथा संयुक्त राष्ट्र सीमाशुल्क से प्राप्त आयात सांख्यिकी प्रस्तुत करने और उसे सार्वजनिक फाइल में रखने का अनुदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने से अपने को बचा लिया जो प्राधिकारी द्वारा दिये गये अनुदेशों का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए प्राधिकारी को चाहिए कि वे इन आयात आंकड़ों की अनदेखी कर दें। यदि प्राधिकारी इस आयात सांख्यिकी पर विचार करने का निश्चय करते हैं तो हम डीजीएडी से अनुरोध करते हैं कि वह कृपया डीजीसीआईएस आंकड़े सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करें।

प्राधिकारी द्वारा जांच

29. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विविध प्रस्तुतिकरणों का प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है:
- क. इस तर्क के संबंध में कि लेनदेनवार आयात सांख्यिकी का प्रकटन हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि आवेदनपत्र प्रारूप में लेनदेनवार आयात आंकड़ों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने बालाजी डाटा इन्फोर्मेशन सर्विसेज से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया है और इन आंकड़ों पर आधारित सूचना के अगोपनीय पाठ का सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन कर दिया है।
- ख. इस तर्क के संबंध में कि आयात सांख्यिकी में सार्वजनिक सुनवाई के समय परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी की यह सुस्थापित परम्परा रही है कि वे जांच के दौरान डीजीसीआईएस एंड एस से आंकड़े प्राप्त करते हैं और निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसकी जांच करते हैं। वास्तव में कार्रवाई के दौरान प्राधिकारी को डीजीसीआईएस से लेनदेनवार सूचना प्राप्त हुई जिसका जांच के दौरान विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के दौरान कुछ कमियां नोट की गई थी और इस वस्तु के आयातकों से सम्पर्क करके आयातों के स्रोत (जिसका उल्लेख लेनदेनवार डीजीसीआईएस आंकड़ों में किया गया था) का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा आगे और अधिक जांच की गई। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया था कि जांच की अवधि के दौरान यूएसए और यूके से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया गया है और उन्होंने यूएस सीमाशुल्क से प्राप्त जानकारी तथा यूरो स्टेट आंकड़ों को संलग्न किया है। डीजीसीआईएस लेनदेनवार आंकड़ों की जांच के दौरान यह नोट किया गया कि उन तीन खेपों में से जहां यह नोट किया गया था संबद्ध वस्तु का आयात गैर संबद्ध देश से किया गया है, प्रविष्टियों की दो बिलों की गहन जांच से यह सुझाव मिला कि यह संबद्ध वस्तु केवल संबद्ध देश से ही आयात की गई थी। एक मामले में आयात की गई सम्बद्ध वस्तु की प्रविष्टि संख्या, तारीख तथा मात्रा आयातक आंकड़ों से मेल खाती थी जबकि दूसरे मामलों में तारीख मात्रा तथा प्रविष्टि बिल के 6 अंक सहयोगकर्ता आयातक से मेल खाते थे। डीजीसीआईएस आंकड़ों में प्रदर्शित यूके से सम्बद्ध वस्तु की आयातित एक खेप के संबंध में आयातक उत्तर से यह नोट किया गया था कि उन्होंने ऐसी किसी वस्तु का आयात यूके से नहीं किया है। बाद में, प्रत्युत्तरदाता आयातक आंकड़ों से इस बात की भी संपुष्टि हुई थी कि उक्त सम्बद्ध वस्तु केवल चीन जन.गण से है।
- ग. डीजीसी आई एंड एस के संव्यवहार वार आंकड़े सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराने के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुरूप डीजीसी आई एस से प्राप्त लेन-देन वार आंकड़े, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि प्रविष्टि संख्या, तारीख, तथा आयातक के नाम युक्त बिल को सार्वजनिक फाइल में नहीं रखा गया है। तथापि, मात्रा एवं मूल्य, विश्लेषण सहित, मात्रा एवं मूल्य के चुनिंदा आंकड़ों को इस अंतिम जांच परिणाम में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

- घ. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि एकल उत्पादक की ओर से अतिरिक्त शुल्क का अधिरोपण करना, जो बाद में कीमतों पर एकाधिकार कर लेगा, और ऐसा करना उपभोक्ताओं के हित के विपरीत होगा, यह नोट किया जाता है कि पाटन रोधी शुल्क का उद्ग्रहण विधि द्वारा सुस्थापित उचित प्रक्रिया का अनुकरण करके किया जाता है और विधि के अंतर्गत यथा-प्राविधानित अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है; न कि केवल घरेलू उत्पादकों के दावे के अनुरूप ही ऐसा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करना है और पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से आयातों को अवरुद्ध नहीं किया जाता है।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

30. प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां यह सुझाव देते हुए भेजीं कि वे निर्धारित स्वरूप और ढंग में सूचना प्रदान करें। जैसा कि इस प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है, मै. डालियान क्लोरेट ने जांच शुरूआत अधिसूचना का प्रत्युत्तर बहुत देर से प्रदान किया तथा प्रत्युत्तर अवधि से काफी बाहर निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। तथापि प्राधिकारी ने उसे आगे की जांच के लिए स्वीकार कर लिया। जांच की प्रक्रिया के दौरान यह नोट किया गया कि उस प्रत्युत्तर में कई कमियां थीं और तदनुसार, निर्यातक को उसकी कमियां दर्शाते हुए एक त्रुटिपत्र यह सुझाव देते हुए जारी किया गया कि वह उन त्रुटियों में एक निश्चित समय सीमा के अंदर सुधार कर लें। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त प्रत्युत्तर में भी कमियां थीं। प्रत्युत्तर की जांच करने पर यह नोट किया गया कि प्रश्नावली में पूछी गई जानकारी निर्यातक प्रश्नावली के स्वरूप और ढंग में प्रदान नहीं की गई थी। विशेष रूप से, भारत को उनकी निर्यात कीमत में दावा किए गए समायोजनों के आधार पर उल्लेख नहीं किया गया था। वास्तव में, अंतरदेशीय मालभाड़ा, सामुद्रिक भाड़े का आधार आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण समायोजनों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया है कि परिशिष्ट 2क निर्यातक प्रश्नावली के स्वरूप और ढंग में प्रदान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा भारत को निर्यातों की मात्रा और मूल्य, जिसका उल्लेख उन्होंने परिशिष्ट 2 और 3 में किया है, अलग-अलग है। निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के अनुरूप अन्य परिशिष्टों के प्रत्युत्तर प्रदान नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयातकों से प्राप्त भुगतान का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि निर्यातक के त्रुटिपूर्ण प्रत्युत्तर को स्वीकार न किया जाए और उस निर्यातक को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान न किया जाए। इस निर्यातक के अतिरिक्त चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने अपनी प्रश्नावली का प्रत्युत्तर देकर इस जांच में सहयोग नहीं दिया है। प्रकटन पश्चात, मै. डालियान क्लोरेट ने प्रस्तुत किया है कि उनके प्रत्युत्तर को प्राधिकारी ने अनुचित रूप से नामंजूर कर दिया गया है क्योंकि वे ही एकमात्र निर्यातक हैं जिसने प्रत्युत्तर दायर किया है। इस मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि मै. डालियान क्लोरेट लिमिटेड निर्यातक प्रश्नावली के स्वरूप और ढंग में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं और इसलिए प्राधिकारी द्वारा उनका प्रत्युत्तर स्वीकार नहीं किया गया है।

घरेलू उद्योग के विचार

31. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित उल्लेख किया है:
- क. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया कि चीन जन गण को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए, इसके लिए उन्होंने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उल्लेख किया:-
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा ऐसी स्थिति में नहीं दिया जा सकता है जहां प्रमुख शेयर धारकों में से एक कम्पनी पर राज्य का स्वामित्व/ नियंत्रण हो- घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया कि यूरोपियन कमीशन ने संगत रूप से यह धारित किया है कि ऐसे मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता

है जहां राज्य के स्वामित्व वाली/नियंत्रण वाली कम्पनियों को भारी शेयर है। यह तर्क दिया गया कि केवल विगत के हस्तक्षेपों का प्रश्न ही नहीं है बल्कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने, जो बाजार अर्थव्यवस्था उपचार दिलाने के लिए संगत है, के पश्चात भी राज्य के हस्तक्षेप की संभावना बनी रहेगी।

- जब तक चीन के प्रत्युत्तरदाता निर्यातक यह स्थापित नहीं कर देते हैं कि प्रमुख इनपुटों की कीमतें बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित करती हैं तब तक उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है:—
घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि “पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित बाजार मूल्यों” की इस अर्थ में व्यापक व्याख्या की गई है कि इन इनपुटों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से तुलनीय होनी चाहिए। घरेलू उद्योग का तर्क है कि यह तथ्य कि ये कीमतें चीन जन गण में प्रचलित कीमतों से तुलनीय हैं, सकल रूप से अपर्याप्त है।
- अधिकांश इनपुटों में उपयोग में आने वाली वस्तुएं शामिल हैं: घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि किसी उत्पाद का उत्पादन करने के लिए विद्युत और ईंधन उपयोगिता की प्रमुख वस्तुएं होती हैं। सर्व सम्मति से, जब विद्युत आपूर्तिकर्ता राज्य स्वामित्व वाली कम्पनी हो तो ईंधन आपूर्तिकर्ता के सम्बंध में अपर्याप्त जानकारी ही उपलब्ध होगी। निर्यातक द्वारा यह स्थापित नहीं किया गया है कि उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमतें बाजार मूल्य को प्रतिबिम्बित करती हैं।
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक उनकी बहियों का अंकेक्षण अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप न किया जाए: घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चीन के निर्यातकों ने बार-बार यूरोपियन आयोग द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा ऐसी स्थिति में अस्वीकार करने का विरोध किया है, जहां चीन के निर्यातक अपनी बहियां चीन के जीएपी के अनुरूप स्थापित करने में अक्षम हैं। ऐसे मामलों में चीन की कम्पनियां यह तर्क रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करने की जरूरत पर जोर देना कानून से परे है। यूरोपीय आयोग ने यह धारित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों के अनुपालन पर जोर देने की जरूरत वार्षिक रिपोर्ट में अभिव्यक्त राजस्वों और व्ययों की उपयुक्तता एवं परिसम्पत्तियों एवं देयिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यूरोपीय कमीशन के अनुसार जब तक बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप नहीं हैं तब तक लेखाओं की विश्वसनीयता स्थापित नहीं की जा सकती है।
- बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब भी नहीं प्रदान किया जा सकता है जब सभी पैरामीटरों में से केवल एक पैरामीटर ही पूरा होने से बच जाता है: घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया कि यूरोपीय आयोग ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक चीन के निर्यातक नियम के अंतर्गत सभी पैरामीटरों में खरे नहीं उतर जाते हैं।
- दायित्व/उत्तरदायित्व: घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह स्थापित करने की जिम्मेदारी प्राधिकारी की नहीं है कि प्रत्युत्तरदाता कम्पनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था माहौल के अंतर्गत प्रचालन कर रही हैं और वे बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार दिए जाने की हकदार हैं। इसके विपरीत, चीन के प्रत्युत्तरदाता निर्यातकों को यह स्थापित करना चाहिए कि वे बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के अंतर्गत प्रचालन कर रहे हैं।
- रूपान्तरण: घरेलू उद्योग द्वारा तर्क दिया गया है कि ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयर धारकों ने अपनी उत्पादन सुविधाएं स्वयं स्थापित नहीं की हैं, परंतु वह सुविधा किसी अन्य पक्षकार से प्राप्त कर ली हैं तो उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है जब तक बदलाव की प्रक्रिया दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाती है।
- घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ऊपर उल्लिखित कई शर्तों को पूरा करने में चीन के निर्यातकों द्वारा असफल रहना यह धारित करने के लिए पर्याप्त है कि चीन प्रत्युत्तरदाता कम्पनियों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और इस कारण सामान्य मूल्य का निर्धारण पैरा. 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

ख. घरेलू उद्योग ने पुनः उल्लेख किया है कि चीन के किसी भी निर्यातक ने उनके साथ बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार किए जाने का दावा नहीं किया है। अतः प्राधिकारी इस बात पर विचार नहीं कर सकते हैं कि विचाराधीन उत्पाद से

सम्बंधित एक या एक से अधिक कम्पनी को अथवा विचाराधीन उत्पाद से सम्बंधित चीन की अर्थव्यवस्था को वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार दिया जा सकता है।

- ग. कच्चा माल सोडियम क्लोरेट है और उसे सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नहीं अपनाया जा सकता है। गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में प्राधिकरण को तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था की लागत या कीमत पर विचार करना अपेक्षित होता है।
- घ. डालियान क्लोरेट कम्पनी द्वारा किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण पर इस कारण से विचार नहीं किया जाना चाहिए कि कम्पनी ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर तथा प्रस्तुतिकरण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दर्ज नहीं किए हैं। वास्तव में कम्पनी ने मौखिक सुनवाई के समय कोई मौखिक प्रस्तुतिकरण भी नहीं किया है। सुनवाई के समय मै. दुआ एसोसिएट्स ने स्पष्टतः यह उल्लेख किया कि वे सालर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- ङ. चीन के निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और विनिर्माण प्रक्रिया तथा उसके प्रभाव में कोई अंतर स्थापित नहीं किया है। भारत में कोई आयातक याचिकाकर्ता और विदेशी उत्पादक के बीच निर्माण प्रक्रिया में भिन्नता की अवस्थिति स्थापित नहीं कर सकता है और न ही कोई आयातक उसके प्रभाव का परिभाषीकरण कर सकता है जैसा कि माननीय सीईएसटीएटी द्वारा निर्णीत ए आई आई जी एम ए बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी-2000 (119) ई एल टी 333 (ट्रि) के मामले से स्पष्ट है।
- च. आयातक सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना प्रदान नहीं कर सकता है और भारत में आयातक अथवा उपभोक्ता सामान्य मूल्य की परिशुद्धता अथवा अन्यथा का प्रश्न उठाने के हकदार नहीं है।
- छ. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समान मदों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना होता है। घरेलू उद्योग ने समान मदों का उत्पादन और उसकी बिक्री की है और इस कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य मूल्य पर विचार नियमावली के अनुबंध-7 के आधार पर करना अपेक्षित होता है।
- ज. यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक बार इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पैरा-7 लागू होना चाहिए तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को चीन की लागत पर विचार करना अपेक्षित नहीं होता है। तब वह पूरी तरह से असंगत हो जाता है।
- झ. याचिकाकर्ता ने सत्यापन योग्य सूचना के आधार पर दावा किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अब उसका सत्यापन कर लिया है और इस कारण वे सत्यापित आंकड़ों के आधार पर तथ्यों पर विचार कर सकते हैं। साक्ष्यों की गोपनीयता की संरक्षा नियम-7 के अंतर्गत की जाती है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है।
- ञ. याचिकाकर्ता ने अपने अनुभव के आधार पर सूचना प्रदान की है। याचिकाकर्ता के लिए कच्चा माल सोडियम क्लोरेट है और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उसे ही अपनाया गया है। गैर बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी को बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में प्रचलित कीमत या लागत पर विचार करना अपेक्षित होता है।
- ट. कम्पनी ने निर्धारित व्ययों के आबंटन और प्रभाजन के लिए उत्पादन या कारोबार अनुपात को अपनाया है। उत्पादन में कमी होने के परिणामस्वरूप, कम्पनी ने व्यय के न्यूनतर हिस्से को प्रभारित किया है और इसलिए जांच की अवधि के दौरान उत्पादन की लागत कम उत्पादन के कारण अधिक नहीं है।
- ठ. विगत में इस उत्पाद पर प्रभारित व्यय का हिस्सा जांच की अवधि के दौरान प्रभारित व्यय के हिस्से से अधिक था। ऐसा उत्पादन में कमी के कारण हुआ। अतः, उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप कम्पनी ने व्यय के न्यूनतर हिस्से को प्रभारित किया है और इसलिए जांच की अवधि के दौरान उत्पादन की लागत कम उत्पादन के कारण अधिक नहीं है।
- ड. निर्दिष्ट प्राधिकारी वास्तविक परिवर्तन लागत पर विचार नहीं करते हैं बल्कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सामान्य परिवर्तन लागत को अपनाते हैं। ऐसा मामला होने पर किसी भी हाल में यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि विनिर्मित सामान्य मूल्य अधिक होना चाहिए।
- ढ. उन्होंने प्राधिकारी से मै. डालियान क्लोरेट लिमिटेड से प्राप्त निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर को नामंजूर कर देने का अनुरोध किया है।

आयातकों/उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

32. सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के सम्बंध में आयातकों/उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण निम्नलिखित हैं:
 - i. उत्पाद के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए "बाजार" एवं "गैर बाजार अर्थव्यवस्था" संगत नहीं है और उनका कोई सम्बंध नहीं है।
 - ii. बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में लागत या कीमत उपलब्ध है और वह प्रदान नहीं कराई गई है।
 - iii. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य का निर्धारण गलत ढंग से किया है। सी एन वी 1.97 अमरीकी डालर के बराबर उच्च नहीं हो सकती है।
 - iv. समायोजन के पश्चात बाला जी डाटा सूचना सेवा से आंकड़े प्राप्त करना सही एवं विश्वसनीय नहीं हो सकता है।
 - v. यह दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं प्रदान कराया गया है कि सामान्य मूल्य, निवल निर्यात कीमत से अधिक है।
 - vi. याचिकाकर्ता और चीन के विनिर्माणकर्ताओं की विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर है। याचिकाकर्ता विनिर्माणकर्ता पहले कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोरेट का प्रयोग करते हैं और फिर उसे सोडियम परक्लोरेट में परिवर्तित करते हैं। जबकि चीन जन.गण के विनिर्माता संबद्ध वस्तु का विनिर्माण सोडियम क्लोरेट में सामान्य लवण और जल का परिवर्तन करके सोडियम क्लोरेट से सोडियम परक्लोरेट का विनिर्माण करते हैं। याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत का समायोजन तदनुसार किया जाना चाहिए।
 - vii. विद्युत लागत, एस जी ए व्यय आदि सहित सभी परिवर्तन लागत का निर्धारण घरेलू उद्योग की लागत शीट के आधार पर किया गया है। चीन में विद्युत लागत वही नहीं है जो विद्युत लागत भारत में है।
 - viii. परिवर्तन लागत इतनी अधिक नहीं हो सकती है जितनी याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत की है।
 - ix. पाटन मार्जिन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है क्योंकि सामान्य मूल्य तथा फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए प्राधिकारी को साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
 - x. सामान्य मूल्य का दोषपूर्ण निर्धारण किया गया है और उस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पुनः विचार किए जाने की जरूरत है। घरेलू उद्योग ने विनिर्मित सामान्य मूल्य जानबूझकर और कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। संभवतः, घरेलू उद्योग द्वारा परिकल्पित 92.27/रुपये प्रति किग्रा. का विनिर्मित सामान्य मूल्य जांच की अवधि के दौरान असामान्य रूप से उच्च उत्पादन लागत अर्थात् क्षमता उपयोग से 40 प्रतिशत के कारण हुआ है।

प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण. के बारे में बाजार अर्थव्यवस्था दावे की जांच

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत और अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांच में चीन जन गण को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। चीन जन.गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है, परन्तु यह पाटनरोधी नियमावली में दी गई शर्तों के अनुरूप व्यक्तिगत निर्यातकों/उत्पादों या निर्यातक देशों द्वारा पूर्ववधारणा के खंडन के अधीन है।
34. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की पूर्ववधारणा का खंडन किया जा सकता है, यदि चीन जन.गण. में निर्यातक/उत्पादक पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर सूचना एवं पर्याप्त साक्ष्य प्रदान कराते हैं तथा इसके विपरीत तथ्य स्थापित करते हैं। सम्बद्ध वस्तु के चीन जन गण से सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बाजार

अर्थव्यवस्था प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में पैरा 8 के उप-पैराग्राफ (3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रदान कराएँ जिससे कि प्राधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया-पर विचार करने में सक्षम हो सकें कि क्या:-

- चीन जनगण में सम्बंधित फर्मों की कच्चेमाल सहित कीमत, लागत और इनपुट, प्रौद्योगिकी की लागत एवं श्रम आउटपुट, बिक्री एवं निवेश से सम्बंधित के निर्णय इस सम्बंध में देश के किसी भी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना; मांग और आपूर्ति को प्रदर्शित करते हुए बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में किए जाते हैं और क्या प्रमुख इनपुटों की लागत बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
- ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, खासकर परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते में डाले गए, विनिमय व्यापार और ऋण की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान, से आगे ले जाए गए महत्वपूर्ण विकृति के अध्यधीन है।
- ये फर्में दिवालियापन और सम्पत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों का प्रचालन करने के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता प्रदान करती हैं।
- विनिमय दर परिवर्तन, बाजार दर के अनुसार किए जाते हैं।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरुआत नोटिस के परिणामस्वरूप चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्धारित समय-सीमा के अंदर बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रत्युत्तर सहित किसी भी प्रश्नावली का प्रत्युत्तर निर्धारित स्वरूप और ढंग से प्रस्तुत नहीं किया और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पूर्वावधारणा से छूट मांगी।

चीन जन गण से निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण

36. चूंकि चीन के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर नहीं भेजा है, इसलिए प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का आकलन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- 1 के पैरा 7 के आधार पर किया। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- 1 के पैरा 7 में निम्नलिखित प्रावधान है-

"गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण तृतीय देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर अथवा उक्त तृतीय देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत, जहां यह संभव नहीं है, अथवा किसी अन्य उत्तरदायी आधार पर, जिनमें समान उत्पाद के लिए भारत में देय या वास्तविक रूप से प्रदत्त कीमत शामिल हो, जिसमें तर्कसंगत लाभ मार्जिन को भी शामिल किया जाए, के आधार पर किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध देश के विकास एवं प्रश्नाधीन उत्पाद के स्तर को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत ढंग से एक समुचित तृतीय देश बाजार अर्थव्यवस्था का चयन किया जाएगा और इस चयन के समय यदि कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराई जाती है तो उस पर भी समुचित ध्यान दिया जाएगा। जहां उपयुक्त हुआ लेखाओं को समान मामले में किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के सम्बंध में की गई जांच के अनुरूप लिया जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के उपर्युक्त चयन के बारे में जांच के पक्षकारों को बिना किसी अतर्कसंगत विलम्ब के तत्काल सूचना दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त समयावधि प्रदान की जाएगी।

37. प्राधिकारी ने उल्लेख किया कि जांच शुरुआत अधिसूचना में आवेदक ने दावा किया कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाए और इस कारण चीन जन.गण. के सम्बंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाए। आवेदक ने यह तर्क देते हुए प्रस्तुत किया कि उनके पास बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए भारत को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जा सकता है। इस दावे का किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा विरोध नहीं किया गया है।

38. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चीन जन.गण. से सम्बद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और पुनः यह नोट करते हुए कि चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए किसी उपयुक्त तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सूचना/आंकड़े रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के द्वितीय परन्तुक में दी गई शर्तों के अनुसार उपलब्ध "तर्कसंगत आधार" पर किया है। तदनुसार विचाराधीन उत्पाद के एक्स-वर्क्स सामान्य मूल्य का निर्धारण विधिवत समयोजित निर्मित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित क्रियापद्धति के अनुरूप किया गया:-

चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति

39. प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण निम्नलिखित आधार पर किया है:-

- क. प्रमुख इनपुटों की कीमतों पर, प्रचलित अंतराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर विचार किया गया।
- ख. उत्पादन के प्रति यूनिट कच्चे माल की खपत और समपरिवर्तन लागत पर विचार, रिकार्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी आंकड़ों के आधार पर अर्थात् घरेलू उद्योग की सूचना/आंकड़ों के आधार पर किया गया है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत का समायोजन चीन के उत्पादकों द्वारा कच्चे माल के प्रयोग के अनुरूप किया जाना चाहिए, इस बारे में यह नोट किया जाता है कि चीन के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को स्वीकार नहीं किया गया है और इसलिए सामान्य मूल्य को चीन के आंकड़ों के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत यथा-अधिदेशित रिकार्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी/आंकड़ों पर अर्थात् घरेलू उद्योग/सूचना के आधार पर विचार किया है इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए याचिकाकर्ता की वास्तविक उत्पादन लागत को नहीं अपनाया है। याचिकाकर्ता द्वारा चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए गैर क्षतिकारी कीमत के प्रयोजन के लिए अपनाई गई मानकीकृत उत्पादन लागत पर विचार किया गया है।
- ग. बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत की गणना रिकार्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी/आंकड़ों के आधार पर अर्थात् घरेलू उद्योग की सूचना/आंकड़ों के आधार पर की गई।
- घ. लाभ को, ब्याज का अपवर्जन करते हुए फैक्टरी बाह्य लागत पर 5 प्रतिशत की दर से गिना गया।

40. इण्डियन एक्सलोसिबज लिमिटेड के इस तर्क के सम्बंध में कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश की लागत और कीमत दोनों ही उपलब्ध हैं, यह नोट किया जाता है कि इण्डियन एक्सलोसिबज लिमिटेड द्वारा ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। वेब पर की गई खोज में भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऐसी कोई सूचना नहीं दर्शायी गई है।

41. सालर इण्डस्ट्रीज के इस तर्क के सम्बंध में कि निर्मित सामान्य मूल्य एक छलावा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का परिकलन सकारात्मक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिना किसी आधार के यह भी परिकल्पना की गई है कि केवल सोडियम क्लोरेट पर ही लागत का बड़ा हिस्सा व्यय होता है।

42. विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य का निर्धारण **** रुपये प्रति कि.ग्रा. **** अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. के रूप में किया गया है।

निर्यात कीमत

43. चूंकि सम्बद्ध वस्तु के चीन जून गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से निर्यातक प्रश्नावली के स्वरूप और ढंग में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) में दिए गए "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर किया है। इस उद्देश्य के लिए आयात की मात्रा के संबंध में डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आकड़ों पर भरोसा किया गया। सीआईएफ कीमतों का समायोजन रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। तदनुसार, निर्यात कीमत का समायोजन समुद्री भाड़ा, चीन में पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, बैंक कमीशन के लिए किया गया है।
44. इण्डियन एक्सप्लोसिब्स लिमिटेड ने सेकेंडरी स्रोत डाटा को अपनाए जाने का विरोध किया है। जबकि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी को अपनाना न्यायोचित ठहराता है और वर्तमान निर्धारण डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आकड़ों के आधार पर है।

पाटन मार्जिन

45. उपर्युक्त यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया गया है। यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक तथा महत्वपूर्ण है।

विवरण	रुपये/कि.ग्रा.	अमरीकी डॉलर/प्रति कि.ग्रा.
सामान्य मूल्य	****	****
निबल निर्यात कीमत	****	****
पाटन मार्जिन	****	****
पाटन मार्जिन (%)	****	****
पाटन मार्जिन % रेंज	20-30	20-30

च. क्षति निर्धारण**घरेलू उद्योग के विचार**

46. क्षति एवं कारणात्मक सम्बंधों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए—

क. आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप में भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

ख. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि किए जाने के बावजूद उसकी बिक्री में काफी गिरावट आई है।

ग. चीनी के पाटित आयातों का बाजार हिस्सा समस्त क्षति अवधि में निरंतर बढ़ा है और इसमें जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जबकि उसी अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में

गिरावट आई है।

- घ. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन हो रहा है।
- ङ. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का अवनमन हो रहा है और वे उसकी कीमतों को बढ़ने से रोक रहे हैं, परन्तु यदि पाटन नहीं होता तो उसकी कीमतों में वृद्धि होती।
- च. उत्पादन क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, मालसूची, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर अर्जन, नकदी प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में अत्यधिक कमी आई है तथा यह नकारात्मक स्तर तक पहुँच गया।
- छ. देश में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य आपूर्तिकर्ता न होने के कारण बाजार हिस्सा, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट तथा मालसूची में वृद्धि स्पष्टतः देश में पाटित आयातों के कारण ही हुई है।
- ज. घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक यौन से आयात कीमत तथा इनपुट कीमतें हैं। अतः कीमत अवनमन एवं निग्रहण बाजार में उत्पादों के पाटन के कारण हुआ है।
- झ. घरेलू उद्योग का विकास मात्रा एवं कीमत दोनों रूपों में विपरीत रहा।
- ञ. घरेलू उद्योग भारतीय मांग के पर्याप्त अंश को पूरा करने में सक्षम था। आयातों में वृद्धि को घरेलू उद्योग में दक्षता के अभाव के द्वारा न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है।
- ट. पाटनरोधी शुल्क लगाने से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर रोक लगाने या उन्हें प्रतिबंधित करने का इरादा नहीं है। पाटनरोधी शुल्क का इरादा घरेलू उत्पादकों तथा पाटित आयातों के बीच समान स्तर बनाए रखना है।
- ठ. वर्ष 2010-11 तक क्षमता संवर्धन के बावजूद विपरीत मात्रा प्रभाव नहीं हुआ और यह क्षमता उपयोग स्वयं ही विपरीत मात्रा प्रभाव स्थापित करता है।
- ड. घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच अवधि के दौरान विगत वर्ष की तुलना में गिरावट स्पष्टतः क्षति का निर्धारण करती है।
- ढ. जांच अवधि के दौरान लाभ, उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में गिरावट और आयातों में वृद्धि के साथ-साथ मालसूची में वृद्धि स्पष्टतः क्षति स्थापित करती है।
- ण. विधि में क्षति अवधि के दौरान निष्पादन में धीरे-धीरे गिरावट की अपेक्षा नहीं की जाती है। यदि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आती है तो उसका आशय है कि क्षति हुई है।
- त. यदि ब्याज व्यय और मूल्यहास लागत दोनों को समान स्तर पर ले जाए तब भी घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट नजर आएगी।
- थ. वर्ष 2009-10 में ब्याज लागत और मूल्यहास में पर्याप्त वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता लगभग अनुरक्षित रहती। जांच की अवधि के दौरान ब्याज की लागत में गिरावट से, लाभप्रदायकता में तीव्रता से गिरावट आई और इससे वित्तीय क्षति की स्थिति उत्पन्न हो गई।
- द. जब मौजूदा क्षमता अनुपयुक्त रही तो घरेलू उद्योग को क्षति, क्षमता में वृद्धि के साथ मांग में वृद्धि को पूरा करने की घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण नहीं हुई।
- ध. याचिकाकर्ता द्वारा निर्यात में गिरावट नहीं की गई है। वर्ष 2010-11 में एकवारगी उच्चतर निर्यात थे। यदि इन निर्यातों का अपवर्जन कर दिया जाता है तो यह देखा जा सकता है कि शेष अवधि में निर्यात समान स्तर पर ही बने रहें। यदि उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर अर्जन, नकदी प्रवाह आदि का निर्धारण निर्यातों को प्रथक करके किया जाता है तो ऐसा होते-हुए भी आकड़े दर्शाते हैं कि अत्यधिक गिरावट आई है।
- न. नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू उद्योग को अन्य कारकों से हुई क्षति को अलग करें। अतः यदि यह विचार किया जाता है कि निर्यात निष्पादन ने क्षति विश्लेषण को

प्रभावित किया है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात सूचना को अलग करके निर्यात निष्पादन पर विचार कर सकते हैं।

- प. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2004 (170) ई एल टी 144 (ट्राई—दिल्ली) का सीईएसटीएटी निर्णय पूर्णतया भिन्न निर्णय था और वह वर्तमान मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है। उक्त अवधि में लाभप्रदायकता में अत्यधिक गिरावट स्पष्टतः क्षति स्थापित करती है। इससे अतिरिक्त, उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर अर्जन, नकदी प्रवाह में गिरावट के रूप में भी घरेलू उद्योग को क्षति स्थापित होती है।
- फ. याचिकाकर्ता द्वारा रिपोर्ट किए गए ओपनिंग स्टॉक (अथ भंडार) में टाइपिंग संबंधी गलती है। कंपनियों का अथ भंडार 36 मी.टन था जबकि कम्पनी ने शून्य अथ भंडार की सूचना दी है।
- ब. वर्ष 2008-09 के लिए मूल्यहास आंकड़ों में भी टंकण संबंधी त्रुटि है। शुद्ध किए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रभारित मूल्यहास में वास्तव में कमी आई है।
- भ. यह समझ नहीं आया है कि मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता से क्षति किस तरह होगी। मांग को पूरा कर पाने की घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण उसके उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट नहीं आई होगी। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग देश में मांग को पूरा करने में अक्षम रहता है वहां घरेलू उद्योग के निष्पादन में कम से कम सुधार होता है।
- म. यह नहीं कहा जा सकता है कि लघु आकार के उद्योग को पाटनरोधी विधि के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, समग्र बाजार आकार इस उत्पाद के लिए 16 करोड़ रुपये से अधिक है।
- य. सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का उपशमन करना है ताकि भारतीय बाजार में पक्षपात रहित एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित हो सके, जो सामान्यतः देश के हित में होती है।
- कक. जांच को समाप्त करने का भी कोई आधार नहीं दिया गया है। यह उत्पाद उपभोक्ताओं की समग्र बिजनेस में एक महत्वहीन भाग बनता है।
- खख. इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन केवल भारत, चीन, यूएस और जर्मनी में किया जाता है। यदि घरेलू उद्योग की इस स्तर पर संरक्षा नहीं की जाती है तो घरेलू उद्योग की स्थिति में और अधिक गिरावट आएगी तथा याचिकाकर्ता को यह उत्पाद छोड़ने के लिए प्रासंगिक रूप से बाध्य किया जाएगा। घरेलू उद्योग के जायज हितों की संरक्षा करने के लिए विधियां बनाई गई हैं।
- गग. डीजीसी आई एंड एस आंकड़ों की मांग करना निर्दिष्ट प्राधिकारी की एक सुस्थापित प्रक्रिया रही है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा डीजीसी आई एंड एस के आधार पर प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी डीजीसीआई एंड एस से आंकड़े मांगने की अपनी प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे और उन्हीं पर भरोसा करेंगे। यह उल्लेख करना भी संगत है कि साक्ष्यों की मात्रा और उनकी गुणवत्ता जांच की प्रगति में सुधार लाती है। इस संबंध में पैनल रिपोर्ट के मामले में तथा ग्वाटेमाला-मैक्सिको से ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट डब्ल्यू टी/डीएस 156/आर संबंधी निर्णायक पाटनरोधी शुल्क मामले में डब्ल्यूटीओ के निर्णय का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है।
- घघ. याचिकाकर्ता घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम है। देश में इस उत्पाद की मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण आयातों में वृद्धि नहीं हुई है। आयातों में यह वृद्धि घरेलू कीमतों तथा आयातित उत्पाद की कीमतों के बीच भारी अंतर के कारण हुई है।
- ड.ड. भारतीय मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता से याचिकाकर्ता को पाटित आयातों के विरुद्ध राहत प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता है। घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष से क्षमता उपयोग में भारी गिरावट का सामना किया है। जब मौजूदा क्षमताओं का ही उपयोग नहीं हो पाया है, इसलिए घरेलू

उद्योग को होने वाली क्षति बढ़ती मांग के साथ-साथ अपनी क्षमता में वृद्धि न कर पाने के कारण नहीं हुई होगी।

चच. घरेलू उद्योग की मालसूची तथा बंदी के घटों से संबंधित सूचना स्पष्टतः यह स्थापित करती है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में कमी घरेलू बाजार से आर्डर प्राप्त होने में कमी के कारण आई है। घरेलू उद्योग अपनी मालसूची से अथवा अपनी अनुप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग करके सामग्रियों की आसानी से आपूर्ति कर सकता है।

छछ. आयातक की ओर से यह प्रकल्पना की जाती है कि क्षमता विस्तार निर्यात बाजार के लिए किया गया। वास्तव में घरेलू उद्योग मुख्यतः घरेलू बाजार तक सीमित है। हर हाल में, घरेलू उद्योग को इससे उत्पादन कर नुकसान हुआ है और इस बढ़ती मालसूची का सामना करना पड़ा है।

जज. कंपनी ने इतनी अधिक क्षति पहले कमी भी सहन नहीं करी जितनी क्षति उसे अब हो रही है। चूंकि कंपनी ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, इसका आशय यह नहीं है कि कंपनी को कोई कार्रवाई करने से रोका जाए।

झझ. प्रकटन पश्चात् उन्होंने अपने प्रस्तुतिकरणों में क्षति एवं कारणात्मक संबंध का उल्लेख किया है। आयात आंकड़ों के मुद्दे के संबंध में उन्होंने इस तथ्य को नकार दिया है कि हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणी करने का अवसर दिए बिना ही याचिका में परिवर्तन कर दिया गया और कम उत्पादन के कारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत बहुत अधिक है। उन्होंने पुनः आयातकों द्वारा किए गए इस प्रस्तुतिकरण को नकार दिया है कि वे सम्बद्ध वस्तु की घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात् विवरण में निर्धारित प्रमात्रा आधार पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध किया है। उन्होंने निर्धारित शुल्क का अधिरोपण करने के लिए कारणों के रूप में पाटनरोधी शुल्क संभावित परिहार आयातक द्वारा रिपोर्ट की गई आयात कीमत की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए सीमाशुल्क पत्तन प्राधिकारियों के पास तंत्र का अभाव और इनपुटों की लागत में परिवर्तन के साथ-साथ इस उत्पाद की उत्पादन लागत में भारी परिवर्तन का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि चूंकि यह तथ्यपरक है रुपये का भारी अवमूल्यन हो चुका है इसलिए पाटनरोधी शुल्क अमरीकी डालर के रूप में अधिरोपित की जानी चाहिए।

आयातकों/उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

47. आयातकों/उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए—

- i. घरेलू उद्योग को सम्बद्ध वस्तु के आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई।
- ii. घरेलू उद्योग, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है।
- iii. घरेलू उद्योग वर्ष 2010-11 तक जोड़ी गई नवीन क्षमताओं और आयातों के अतः प्रवाह के बावजूद 88 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम था। यह तो केवल जांच की अवधि के समय में ही हुआ जब क्षमता उपयोग में गिरावट आई। क्षति को क्षति अवधि के समय प्रदर्शित होने की जरूरत है, अतः आयातों एवं क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- iv. सम्बद्ध देशों से आयात में धीमी वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के लाभ वर्ष 2010-11 तक बढ़ रहे थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि आयातों और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- v. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि के बावजूद ब्याज लागत बहुत अधिक बढ़ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षमता विस्तार का वित्त पोषण अधिकांशतः ऋण से किया गया था जिसके कारण प्रति मी.टन उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, परंतु इसे आयातों से नहीं जोड़ा जा सकता है।

- vi. घरेलू उद्योग की मूल्यहास लागत में आधार वर्ष 2008-09 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 142 प्रतिशत वृद्धि हुई, जिसका उत्पादन लागत से सकारात्मक सम्बन्ध है परन्तु इसे आयातों से नहीं जोड़ा जा सकता है। मूल्यहास में आकस्मिक गिरावट से भौतिक परिसम्पत्तियों का बेचा जाना प्रदर्शित होता है जिसकी जांच की जानी चाहिए।
- vii. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में मांग में कुल वृद्धि के अनुपात में अपनी क्षमता में विस्तार नहीं किया। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में 25 प्रतिशत वृद्धि की जबकि मांग में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- viii. घरेलू उद्योग के लाभ में वर्ष 2009-10 में तब सर्वाधिक गिरावट आई जब उतराई आयात की कीमत सर्वाधिक 66.54 रुपये थी।
- ix. निर्यात मांग में गिरावट ही वह वस्तु है जो याचिकाकर्ता को जांच की अवधि के दौरान नुकसान पहुंचा रही है। निर्यातों में गिरावट के कारण क्षमता उपयोग में गिरावट के लिए आयातों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- x. केवल जांच की अवधि के दौरान ही क्षति और नकारात्मक आर ओ सी ई हुआ। केवल जांच की अवधि के दौरान कथित क्षति के आधार पर ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इस संदर्भ में इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निदिष्ट प्राधिकारी 2004 (170) ई एल टी, 144 (ट्राइ-दिल्ली) के मामले में सीईएसटीएटी द्वारा दिये गये निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है।
- xi. वर्ष 2008-09 के दौरान याचिकाकर्ता का उत्पादन 1288 मी.टन था जबकि उसी अवधि के दौरान उसकी बिक्री 1319 मी.टन थी। तथापि, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-09 के दौरान याचिकाकर्ता का अथ भंडार शून्य था।
- xii. क्षमता, मूल्यहास और निवल अचल परिसंपत्तियों के बीच कोई सह सम्बन्ध नहीं है।
- xiii. कारणात्मक सम्बन्ध बिलुप्त है। घरेलू उद्योग यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा कि इतने कम कीमत वाले आयातों से उन्हें वास्तव में क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण उच्च मांग के समय प्रयोक्ता की जरूरत को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता रही है।
- xiv. भारत में इस उद्योग का समग्र मूल्य 6.50 करोड़ रुपये से 7.00 करोड़ रुपये तक से अधिक नहीं है। बाजार के इतने छोटे आकार पर विचार करते हुए डीजीएडी को यह विचार करना चाहिए कि क्या इतने लघु उत्पाद को भी संरक्षात्मक उपाय के अधिरोपण की जरूरत है।
- xv. याचिकाकर्ता को क्षति उसके कम निर्यात निष्पादन तथा याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और बेचे गये अन्य उत्पादों के बहुत कम निष्पादन के कारण हुई है।
- xvi. क्षति के प्रभावों का प्रदर्शन इस उद्देश्य के लिए बनाये गये नियमों के अनुबन्ध-II के पैराग्राफ (iv) में निर्धारित प्राचलों के अनुरूप नहीं किया गया है।
- xvii. घरेलू उद्योग ने न केवल आयातों के सम्बन्ध में आंकड़ों में परिवर्तन किया है बल्कि इसने अपनी पुस्तिका में अपने निजी आंकड़ों में संशोधन भी किया गया है।
- xviii. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु की घरेलू मांग को पूरा करने में अक्षम रहा है इसलिए संबद्ध वस्तु का आयात करना पड़ा। जांच की अवधि के दौरान घरेलू मांग 2042 मी.टन थी जबकि घरेलू उत्पादन घटकर 804 मी.टन रह गया था। चूंकि घरेलू उद्योग एकाधिकारवादी उद्योग है इसलिए मांग और आपूर्ति के इस अंतराल को केवल संबद्ध देश से आयात करके ही पूरा किया जा सकता था।
- xix. घरेलू उद्योग का मुख्य फोकस निर्यात बिक्रियों पर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात बिक्रियों पर अधिक बल देने का मुख्य कारण घरेलू बिक्रियों के विपरीत निवेश पर भारी आय होना है।
- xx. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त क्षमताओं का संवर्धन किया तथापि यह संवर्धन निर्यात बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए था, न कि घरेलू बाजार के लिए। वर्ष 2010-11 में निर्यात बिक्री 392 मी.टन से

- बढ़कर 760 मी.टन हो गयी। अतः, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं में वृद्धि निर्यात बिक्रियों को पूरा करने के लिए की थी न कि घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए और घरेलू उद्योग अब चीन से आयातों में वृद्धि के कारण बाजार हिस्से में उसको होने वाली क्षति के संबंध में क्षति का दावा नहीं कर सकता है।
- xxi. वर्ष 2009-10 में आयातों में भारी वृद्धि हुई, जब संबद्ध आयात 216 मी.टन से बढ़कर 1234 मी.टन हो गये। वर्ष 2009-10 में ही याचिका दायर क्यों नहीं की गई और यह याचिका तब दायर क्यों की गई जब संबद्ध देशों से आयातों की प्रमात्रा कमोवेश रूप से एक जैसी बनी रही।
- xxii. घरेलू बिक्रियों में 48 प्रतिशत की गिरावट आने के साथ-साथ घरेलू उद्योग ने निर्यात बिक्रियों में 163 प्रतिशत की गिरावट का सामना भी किया है। निर्यात बिक्रियों में आयी गिरावट के कारण लाभ में हुई क्षति के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है।
- xxiii. याचिकाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई आयात की मात्रा याचिकाकर्ता द्वारा किये गये सभी प्रस्तुतिकरणों में अलग-अलग है।
- xxiv. केवल जांच की अवधि के दौरान सहन किये गये तथाकथित घाटे के आधार पर ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को वास्तव में क्षति हुई है।
- xxv. प्रकटन पश्चात एक आयातक ने प्राधिकारी से गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए सामान्य लवण और जल को सोडियम क्लोरेट में परिवर्तन करने की उपयुक्त लागत को ध्यान में रखकर याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत का समायोजन करने का अनुरोध किया है।
- xxvi. प्रकटन पश्चात एक आयातक ने प्रस्तुतिकरण किया है कि घरेलू उद्योग को अपनी ही कारणों से क्षति सहन करनी पड़ रही है और पाटन का घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग एकाधिकारवादी उद्योग है पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ होगा। उन्होंने प्राधिकारी से संदर्भ कीमत आधार पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न प्रस्तुतिकरणों को नोट किया है और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का विश्लेषण रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करके तथा अनुप्रयोज्य विधियों का अनुसरण करके किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों पर संगत पायी गयी सीमा तक विचार किया गया और उन पर इस जांच परिणाम के संगत खंडों में और निम्नलिखित रूप से विचार किया गया है।
49. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि बाजार के छोटे आकार पर विचार करते हुए, प्राधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि क्या इतने छोटे उत्पाद के लिए किसी संरक्षणत्मक शुल्क का अधिरोपण करना उपयुक्त होगा, इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि उद्ग्रहीत पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं का उपशमन करना और घरेलू उद्योग को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाये रखने के लिए पक्षपात रहित अवसर प्रदान करना है। पाटनरोधी विधि बाजार आकार तथा उसके कारोबार के आधार पर घरेलू उद्योग में कोई अंतर नहीं करता है। पाटनरोधी विधि के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने की मांग करने के अधिकार को इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है।
50. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में गिरावट के कारण उसे क्षति हुई है, इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह जांच परिणाम घरेलू उद्योग के केवल घरेलू बाजार में निष्पादन पर आधारित है। निर्यात बाजार में निष्पादन का अपवर्जन कर दिया गया है। क्षति पैरामीटरों का विश्लेषण यह

दर्शाता है कि क्षति अवधि के दौरान आयातों में भी भारी वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन, वर्ष 2010-11 को छोड़कर, जब निर्यात बहुत अधिक हुए थे, संपूर्ण क्षति अवधि में लगभग समान स्तर पर बना रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010 में घरेलू उद्योग के कीमत पैरामीटरों में, जब निर्यात उच्चतर थे, गिरावट आयी है। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि घरेलू उद्योग को दावा की गई यह क्षति निर्यात निष्पादन के कारण हुई है।

51. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने निर्यात बिक्रियों की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2010-11 में अपनी क्षमताओं में विस्तार किया, इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास भारी ऐसी क्षमता थी जिसका उपयोग नहीं किया जाता था। घरेलू उद्योग, कंपनी द्वारा किये गये वर्तमान निर्यातों के बाद भी घरेलू बाजार की उच्चतर मात्रा के अनुरूप उत्पाद और बिक्री कर सकने में संक्षम थी।
52. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु की घरेलू मांग को पूरा करने में असक्षम रहा है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग लगभग समस्त भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी उपाय वह साधन नहीं है जिससे निर्यातों को प्रतिबंधित किया जाता हो बल्कि यह वह साधन है जो, घरेलू उद्योग तथा संबद्ध निर्यातकों दोनों को समान प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करता है। गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए सामान्य लवण और जल को सोडियम क्लोरेट में परिवर्तित करने की उपयुक्त लागत को ध्यान में रखकर याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत का संमायोजन करने के लिए आयातक के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुरूप किया गया है।
53. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण के लिए ऐसे तथ्यों की जांच करनी होगी जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए उनकी कीमत पर प्रभाव और इन आयातों का ऐसी मदों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए-----" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान मदों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से पर्याप्त कीमत अधोरदन हुआ है अथवा क्या इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का भारी मात्रा में अवनमन हुआ है अथवा इससे कीमतों में वृद्धि रुकी है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ी होती।
54. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों जैसे उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक लाभप्रदायकता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन की मात्रा एवं अवधि आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया।
55. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव दोनों की वास्तविक जांच करने का प्रावधान है। पाटित आयातों के प्रभाव की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह परीक्षण करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत से संगत रूप से पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटित आयातों का कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह परीक्षण करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत अधोरदन किया गया है, अथवा इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का अन्यथा भारी मात्रा में निग्रहण हो रहा है, अथवा वे कीमतों को बढ़ने से रोक रही है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में हुई होती।
56. उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) निम्नलिखित उल्लेख है:-
 "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक तथ्यों तथा उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अन्य सभी कारकों जिसमें बिक्री, लाभ, आउट-पुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में प्राकृतिक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने

वाले तथ्यों, पाटन के मार्जिन की वास्तविक मात्रा तथा त्रकदी प्रवाह पर संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूची, रोजगार, वेतनवृद्धि, पूजीनिवेश, उगाहन की क्षमता का मूल्यांकन किया जाना शामिल होगा।

57. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने अनुबंध-II (iv) तथा उसके अधीन बने नियमों के अनुसार ऐसे अन्य तथ्यों पर भी विचार किया है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री प्रमात्रा, भंडार, लाभप्रदायकता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और उसका मार्जिन आदि।

मांग तथा बाजार हिस्सा

58. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग का आकलन करने के उद्देश्य के लिए भारत में कुल आयात में घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को शामिल किया गया है। उसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	1,023	770	872	481
2	संबद्ध देश-आयात	मी.टन	628	1,159	1,244	1,427
3	कुल मांग/खपत	मी.टन	1,651	1,929	2,116	1,908

59. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति रही है।
60. इंडियन एक्सप्लोसिव ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इस मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि घरेलू उद्योग भारतीय मांग के एक बड़े हिस्से को पूरा कर सकती थी। किसी भी हाल में घरेलू मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण घरेलू उद्योग को नियमों के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने से मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं बल्कि उन्हें उन कीमतों पर होने की अनुमति देना है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति न पहुंचे।

घ. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

61. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या उत्पादन के संगत रूप से या भारत में खपत के रूप में भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य के लिए प्राधिकारी ने डी जी सी आई एस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा का विश्लेषण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
1	कुल आयात	मी.टन	628	1,159	1,244	1,427
2	घरेलू	मी.टन	628	1,159	1,244	1,427
3	मांग में बाजार हिस्सा	%	61.97	39.92	41.21	25.21
4	घरेलू उद्योग की बिक्री	%	61.97	39.92	41.21	25.21

5	सम्बद्ध देश	%	38.03	60.08	58.79	74.79
6	कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00
7	उत्पादन के सम्बंध में चीन के आयात	%	48.76	99.40	70.80	177.49

62. यह नोट किया जाता है कि:-

- i. आयातों में आधार वर्ष में हुए 628 मी.टन की तुलना में जांच अवधि में 1,427 मी.टन की निरपेक्ष वृद्धि हुई। इस प्रकार इनमें आधार वर्ष की तुलना में 127 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि बहुत ज्यादा और वास्तविक है।
 - ii. सम्बद्ध वस्तु के लिए जांच की अवधि में मांग में आधार वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु उसी अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से पाटित आयातों में यह वृद्धि 127 प्रतिशत तक हुई है। निरपेक्ष रूप में आयातों में यह वृद्धि देश में उत्पाद की मांग की तुलना में अननुपातिक रूप से बहुत अधिक है।
 - iii. सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु का आयात भारत में सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया। इसमें क्षति अवधि के दौरान 129 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित हुई।
 - iv. भारत में उत्पाद की मांग में सम्बद्ध वस्तु का बाजार हिस्सा बहुत अधिक बढ़ा है जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट इस तथ्य के बावजूद आई है कि घरेलू उद्योग सम्बद्ध वस्तु का घरेलू बाजार में एकमात्र उत्पादक है। चीन का बाजार हिस्सा जो आधार वर्ष में 38 प्रतिशत था, बढ़कर जांच की अवधि में 75 प्रतिशत हो गया इस प्रकार इसमें क्षति अवधि में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
63. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि सम्बद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में देश में इस उत्पाद के उत्पादन और खपत की तुलना में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सम्बद्ध देश से आयात में महत्वपूर्ण विपरीत मात्रा प्रभाव प्रदर्शित हुआ है।

ज. आयातों का कीमत प्रभाव

64. पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा पर्याप्त मात्रा में कीमत अधोरदन किया गया है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का पर्याप्त मात्रा में निग्रहण किये जाने पर पड़ेगा अथवा क्या इससे कीमतों में वृद्धि रुकेगी, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती। पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण कीमत अधोरदन, कीमत निग्रहण और कीमत मंदन, यदि कोई, के संदर्भ में किया गया है।

कीमत अधोरदन

65. इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन हो रहा है प्राधिकारी ने आयातों की उतराई कीमत की घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण से तुलना की है। प्राधिकारी ने निवल बिक्री प्रापण का निर्धारण बिक्री कीमत पर विचार कर एवं शुल्क, छूट, डिस्काउंट और कमीशन का अपवर्जन करते हुए किया है। इस परिकलन में घरेलू उद्योग की समस्त घरेलू बिक्री मात्रा को शामिल किया गया है। आयातों की उतराई कीमत का निर्धारण भारत औसत सी आई एफ आयात कीमत, एक प्रतिशत उतराई प्रभार और लागू आधारभूत सीमा शुल्क पर विचार करते हुए किया है। निवल बिक्री प्रापण और आयातों की

उत्तराई कीमत के बीच तुलना की गई थी। प्राधिकारी ने भारित औसत कीमत अधोरदन का निर्धारण पाटित आयातों द्वारा किया है।

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2009-10 से संबद्ध वस्तु की उत्तराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत अधिक कम है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया जा रहा है जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है।

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जांच की अवधि)
आयातों की उत्तराई कीमत	रुपये/किलोग्राम	71.26	61.07	59.03	62.81
निवल बिक्री कीमत	रुपये/किलोग्राम	***	***	***	***
अनुक्रमणिका		100	112	107	103
कीमत अधोरदन	रुपये/किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन(%) रेंज		0-10	20-30	20-30	10-20

67. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के संबद्ध आयातों की उत्तराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है इसके परिणामस्वरूप भारी कीमत अधोरदन हुआ है।

कीमत-अधोबिक्रयण

68. निम्नलिखित तालिका से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

देश/निर्यातक	यूनिट	चीन
उत्तराई कीमत	रुपये/किलोग्राम	62.81
गैर क्षतिकारी कीमत	रुपये/किलोग्राम	***
कीमत-अधोबिक्रयण राशि	रुपये/किलोग्राम	***
कीमत-अधोबिक्रयण %	%	***
कीमत-अधोबिक्रयण % रेंज		10-20

कीमत निग्रहण/अवनमन

69. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का निग्रहण अथवा अवनमन कर रहे हैं और क्या इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण हो रहा है अथवा ये कीमतों को बढ़ने से रोक रही है जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुआ होता, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में लागत एवं कीमत में परिवर्तन पर विचार किया है। निम्नलिखित तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है:-

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
1	बिक्री की लागत	रुपये/किलोग्राम	***	***	***	***
	इन्डेक्स		100	108	102	121
2	बिक्री कीमत	रुपये/किलोग्राम	***	***	***	***
	इन्डेक्स		100	112	107	103

70. यह देखा जाता है कि इस अवधि में (2010-11 को छोड़कर) बिक्री लागत और बिक्री कीमतों, दोनों में वृद्धि हुई। तथापि बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत कम थी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि पाटित आयातों के प्रभाव से कीमत में वृद्धि अवरुद्ध हुई जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती।

झ. घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर

71. पाटन रोधी नियमावली का अनुबंध-II यह अपेक्षा करता है कि क्षति का निर्धारण करने में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का उद्देश्यपरक परीक्षण अंतर्ग्रस्त होगा। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक तथ्यों और उन कारकों का उद्देश्य परक और पक्षपातरहित मूल्यांकन शामिल होगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इसमें बिक्री, लाभ, आउट-पुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश से अर्जन अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों के प्रभावित करने वाले तथ्य, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल-सूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजीगत निवेश उगाहने की क्षमता शामिल है।

72. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों का विवरण निम्नलिखित है:-

i. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग

उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग के सम्बंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नलिखित है:-

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	मी.टन	1,600	1,600	2,000	2000
उत्पादन	मी.टन	1,288	1,166	1,757	804
क्षमता उपयोग	%	80%	73%	88%	40%
घरेलू बिक्री	मी.टन	1,023	770	872	481
कुल मांग	मी.टन	1,651	1,929	2,116	1,908

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री 1023 मी.टन से कम होकर 481 मी.टन हो गई जबकि विचाराधीन उत्पाद की मांग 1651 मी.टन से बढ़कर 1908 मी.टन हो गई। अतः, घरेलू उद्योग की बिक्री में 53 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि विचाराधीन उत्पाद की मांग में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह ऐसी स्थिति में हुआ है जब कि घरेलू उद्योग देश में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि न्यून क्षमता उपयोग केवल घरेलू मांग में कमी के कारण ही नहीं बल्कि निर्यातों में गिरावट के कारण भी हुआ है।

74. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि इसने अपनी क्षमता में वृद्धि की जिससे कि वह बढ़ती मांग को पूरा कर सके। तथापि यह नोट किया जाता है कि क्षमता उपयोग जो आधार वर्ष में 80 प्रतिशत था, जांच की अवधि के दौरान घटकर 40 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार इसमें 50 प्रतिशत की गिरावट आई।

75. घरेलू उद्योग का उत्पादन जो (वर्ष 2008-09 में) 1288 मी.टन था घटकर (जांच की अवधि में) 804 मी. टन रह गया। इस प्रकार इसमें उक्त अवधि में 38 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि उत्पादन बढ़कर वर्ष 2010-11 में 1757 मी.टन हो गया और फिर इसमें गिरावट आई तथा यह 804 मी.टन रह गया। इस प्रकार इसमें वर्ष 2010-11 की तुलना में जांच अवधि में 54 प्रतिशत की गिरावट आई।

ii. बाजार हिस्सा

76. पाटित आयातों का घरेलू बिक्री पर प्रभाव तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर प्रभाव की निम्नवत जांच की गई है:

मांग	मापन की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	61.97	39.92	41.21	25.21
सम्बद्ध देश	%	38.03	60.08	58.79	74.79
कुल	%	100	100	100	100

77. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई, जबकि चीन से किए गए आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित होती है।

78. यह तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने में असफल रहा और बाजार हिस्से में गिरावट उनकी इसी अक्षमता के कारण आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की क्षमता तथा मांग में वृद्धि से क्षमता में संवृद्धि की तुलना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में क्षमता सम्बर्धन देश में इस उत्पाद की वर्तमान और भविष्य में होने वाली मांग को ध्यान में रख कर किया गया है। यह सिद्ध नहीं होता है कि बाजार हिस्से में यह गिरावट इस उत्पाद के उत्पादन तथा उसकी बिक्री करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण आयी है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है।

iii. लाभ, निवेश पर अर्जन और नकदी प्रवाह

79. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और लाभ/हानि का विश्लेषण निम्नवत किया गया है:

विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रूपये/किलोग्राम	***	***	***	***
इन्डेक्स		100	108	102	121
बिक्री कीमत	रूपये/किलोग्राम	***	***	***	***
इन्डेक्स		100	112	107	103
लाभ/हानि	रूपये/किलोग्राम	***	***	***	***
इन्डेक्स		100	168	167	(105)
लाभ/हानि	लाख रूपये	***	***	***	***
इन्डेक्स		100	127	143	(49)
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	लाख रूपये	***	***	***	***
इन्डेक्स		100	102	107	(3)
नगद लाभ	लाख रूपये	***	***	***	***
इन्डेक्स		100	91	94	5
लगाई गई पूंजी	लाख रूपये	***	***	***	***
इन्डेक्स		100	175	150	124
निवेश से अर्जन	%	***	***	***	***
इन्डेक्स		100	59	72	(2)

80. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के लाभ में वर्ष 2010-11 तक वृद्धि हुई और तत्पश्चात सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान इसमें अत्यधिक गिरावट प्रदर्शित हुई। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि बिक्री लागत में जांच की अवधि के दौरान बढ़ोत्तरी हुई, वही जांच की अवधि के दौरान बिक्री कीमत में पिछली वर्ष की समसामयिक अवधि के दौरान इसकी गिरावट की तुलना में गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में बहुत अधिक कमी हुई और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय क्षति सहन करनी पड़ी।

81. क्षति अवधि के दौरान लाभ में कमी होने से निवेश से अर्जन एवं नगद लाभ में भारी गिरावट आई। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निवेश से अर्जन तथा नगद लाभ में इस हद तक गिरावट आई कि इस गिरावट के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नकद घाटा हुआ तथा निवेश से ऋणात्मक अर्जन हुआ।
82. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को कोई घाटा या वित्तीय क्षति नहीं हुई। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री कीमत और लाभ एवं हानि से सम्बन्धित सत्यापित सूचना यह प्रदर्शित करती है कि घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हुआ है।
83. जहां इस तर्क का संबंध है कि लाभ में गिरावट ब्याज लागत और मूल्यहास में बढ़ोतरी के कारण हुई, यह नोट किया जाता है कि ब्याज एवं मूल्यहास के कारण लागत में असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। जांच की प्रक्रिया के दौरान यह नोट किया गया है कि क्षति विवरण में उल्लिखित मूल्यहास की राशि में टंकण संबंधी एक त्रुटि थी। यह भी नोट किया जाता है कि ब्याज पूर्व लाभ और मूल्यहास में भी गिरावट आई है जो स्पष्टतः यह सिद्ध करता है कि लाभ में कमी, मूल्यहास और ब्याज लागत में बढ़ोतरी के कारण नहीं आई है।

iv. मालसूची

84. सम्बद्ध वस्तु की मालसूची से सम्बंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:-

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
1	अथ भण्डार	मी.टन	***	***	***	***
2	इति भण्डार	मी.टन	***	***	***	***
3	औसत भण्डार	मी.टन	21	7	72	121

85. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि होने के साथ-साथ अत्यधिक वृद्धि हुई। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची, सम्बद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। इसके अतिरिक्त, मालसूची में यह वृद्धि उत्पादन में गिरावट के बावजूद आई है।

v. रोजगार एवं वेतन

86. रोजगार एवं वेतन से सम्बंधित स्थिति निम्नलिखित है:-
कंपनी समग्र रूप से

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	इन्डेक्स		100	142	182	182
2	वेतन	लाख रुपये	***	***	***	***
	इन्डेक्स		100.00	181.79	273.56	500.94

87. चूंकि घरेलू उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित रोजगार नहीं है, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा संदत्त रोजगार और वेतन के सम्बंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच, कम्पनी के सभी प्रचालनों के लिए प्राप्त सूचना पर विचार करते हुए, की गई। यह देखा गया कि उक्त अवधि में रोजगार और वेतन दोनों में ही वृद्धि हुई है।

vi. उत्पादकता

88. उत्पादकता से सम्बंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	2008-09	2009-10	2010-11	जांच की अवधि
1	प्रति कर्मचारी उत्पादकता प्रतिदिन	मी.टन	****	****	****	****
	इन्डेक्स		100	75	125	50

89. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष तथा विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान प्रतिदिन उत्पादन में कमी आई है। उत्पादकता में इस गिरावट के लिए विचाराधीन उत्पाद के पाटन के परिणामस्वरूप उत्पादन में आई गिरावट को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

vii. पाटन की मात्रा

90. पाटित आयात जिस सीमा तक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं उसके संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा यह दर्शाती है कि सम्बद्ध देशों के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और महत्वपूर्ण है।

viii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

91. चीन से आयात कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटन आयातों के अलावा अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग को प्रभावित करते हों, यह दर्शाते हैं कि चीन से आयातित माल की उतराई कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है, जो भारतीय बाजार में कीमतों का भारी अधोरदन कारित करते हैं। घरेलू उद्योग के लिए बेंचमार्क सम्बद्ध देश से आयात कीमते होती हैं। विचाराधीन उत्पाद का किसी अन्य देश से आयात नहीं किया गया। इस उत्पाद का कोई अर्थक्षम प्रतिस्थानिक भी नहीं है। इस उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हो रही थी। इस उत्पाद के लिए मांग हो रही थी और यह घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे कीमत निग्रहण का एक उत्तरदायी कारक नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तरदायी एकमात्र कारक चीन जन गण से आयातित उत्पाद की आयात कीमतें तथा घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत है। जैसा कि प्राप्त सूचना से स्पष्ट होता है कि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, घरेलू कीमतों से आयात कीमतें अत्यधिक कम थी जिस कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में वृद्धि, लागत में वृद्धि की तुलना में नहीं कर सका।

ix. वृद्धि

92. सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु की आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। बिक्री और उत्पादन के रूप में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही। इसी तरह, लाभ, नकद लाभ और निवेश से आवक के सम्बंध में घरेलू उद्योग का विकास नगण्य रहा। मांग में भारी वृद्धि होने और सम्बद्ध वस्तु का घरेलू उद्योग एक मात्र उत्पादक होने के बावजूद घरेलू उद्योग नकारात्मक वृद्धि का सामना कर रहा है।

अ. वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष

93. यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और खपत के संबंध में तथा समग्र रूप से पर्याप्त वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन किया जा रहा है। आयात भारी मात्रा में कीमत निग्रहण कर रहे हैं। पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री बाजार हिस्सा, लाभ, नकदी प्रवाह, निवेश पर अर्जन, उत्पादकता और मालसूची में भारी गिरावट आयी है जो अत्यधिक एवं वास्तविक है। अतः, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ट. अन्य ज्ञात तथ्य तथा कारणात्मक संबंध

94. वास्तविक क्षति की मौजूदगी, पाटित आयातों का मात्रा और घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव, कम कीमत पर इसकी बिक्री और कीमत निग्रहण तथा अवनमन प्रभावों, भारतीय नियमावली तथा पाटनरोधी संबंधी करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य संकेतक पैरामीटरों की मौजूदगी की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी ने यह देखने के लिए निम्नवत जांच की कि क्या पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य ऐसे तथ्य हैं जिसने घरेलू उद्योग की क्षति में अपना योगदान दिया हो।

(क) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

95. विचाराधीन उत्पाद का अन्य देशों से कोई आयात नहीं हुआ। अन्य देशों से आयात से घरेलू उद्योग को क्षति भी कारित हुई

(ख) मांग का संकुचन और खपत की प्रणाली में परिवर्तन

96. सम्बंधित उत्पाद की मांग में सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान निरन्तर वृद्धि हुई है। मांग में सम्भावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का सम्भावित कारण नहीं है।

(ग) प्रौद्योगिकी विकास

97. सम्बंधित उत्पादन का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, प्रौद्योगिकी विकास वह तथ्य नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई हो।

(घ) विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधक प्रक्रियायें

98. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधक प्रक्रिया नहीं है जिसकी बजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

(ङ.) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

99. प्राधिकारी को प्रदान कराई गई क्षति सम्बंधी सूचना घरेलू प्रचालनों के लिए है और अतः निर्यात मात्रा में सम्भावित कमी से घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति कारित नहीं हो सकती है।

(च) घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता

100. यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट के परिणामस्वरूप उक्त अवधि में गिरावट आई है। उत्पादन में यह गिरावट देश में उत्पादन के आयतों में वृद्धि के कारण आई है।
101. इण्डियन एक्सप्लोजिब्ज लिमिटेड ने याचिकाकर्ता के इस दावे का विरोध किया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के लिए चीन जन गण से आयातों के अलावा अन्य कोई तथ्य उत्तरदायी नहीं है। तथापि, यह नोट किया जाता है आई ई एल ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों से भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, जांच में पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य ऐसे कारक की मौजूदगी नहीं पाई गई जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो।
102. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य तथ्य यह नहीं प्रदर्शित करते हैं कि इन अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या उत्पादन के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित पैरामीटर यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है:
- (क) संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई जिसके कारण भारत में उक्त उत्पाद की मांग में पाटित आयातों का हिस्सा बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपनी बाजार हिस्से की पहले वाली स्थिति प्राप्त करने से वंचित किया गया।
- (ख) आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन हो रहा था। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में बढ़ोत्तरी करने में सक्षम नहीं हो पाया। अतः आयातों के कारण घरेलू उद्योग के समक्ष उनका कीमत निग्रहण हो रहा था।
- (ग) विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू कीमतों का अधोरदन कर रहे थे, इसके परिणामस्वरूप आयातों की मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई इसका परिणाम यह हुआ कि घरेलू उद्योग का उत्पादन क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा में गिरावट का सामना करना पड़ा।
- (घ) इस कीमत निग्रहण का परिणाम यह हुआ कि लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश से अर्जन के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में कमी आने लगी। अतः उत्पादन के पाटन से घरेलू उद्योग को लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश से अर्जन के रूप में उसके निष्पादन में कमी आई।
- (ङ) घरेलू उद्योग को मालसूची में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।
103. अतः, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।

उ. क्षति की मात्रा एवं क्षति मार्जिन
क्षति मार्जिन

104. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु की निर्धारित गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सम्बद्ध देश से निर्यातों की उतलाई कीमत से की गई। निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नलिखित है:

	रुपये/कि.ग्रा.	अमरीकी डालर /कि.ग्रा.
गैर क्षतिकारी कीमत	***	***
उतलाई मूल्य	***	***
क्षति मार्जिन	***	***
क्षति मार्जिन %	***	***

क्षति मार्जिन % रेंज

10-20

10-20

निष्कर्ष

105. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए मुद्दों और किए प्रस्तुतिकरणों तथा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- क. सम्बद्ध देश से भारतीय बाजारों में सम्बद्ध वस्तु का प्रवेश इससे जुड़े सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सम्बद्ध वस्तु का पाटन हुआ;
- ख. सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु की पाटन मार्जिन न्यूनतम से ऊपर तथा महत्वपूर्ण है;
- ग. सम्बद्ध वस्तु के सम्बंध में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; और
- घ. घरेलू उद्योग को यह वास्तविक क्षति सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई।

भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

106. प्राधिकारी ने यह पाया कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारत में उत्पादन के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय बाजारों में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ दूर होगा, यह घरेलू उद्योग को होने वाले पतन से बचायेगा तथा उपभोक्ताओं को सम्बद्ध वस्तु की व्यापक च्वाइस की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का उन्मूलन करना होता है जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके जो देश के आम हित में हैं। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से सम्बद्ध देशों से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा और अतः, इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता, अब भी, आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए बनाए रख सकते हैं।
107. उपभोक्ता उद्योग पर आयातों के विपरीत प्रभाव के बारे में सौलर इंडस्ट्रीज इंडिया के तर्क के सम्बंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रस्तावित शुल्क का घरेलू उद्योग पर महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव सिद्ध करने के लिए कोई सत्यापन योग्य सूचना प्रदान नहीं कराई गई है। यह भी नोट किया जाता है कि निर्यातों के लिए किये जाने वाले आयात को भारत सरकार द्वारा शुल्क छूट योजना के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का भुगतान न करने की छूट दी गई है और इस कारण प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क इन आयातों को प्रभावित नहीं करेगी।

सिफारिश

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच प्रारंभ की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना देने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया गया। पाटन, क्षति और उनके कारणात्मक संबंध के बारे में पाटनरोधी नियमावली में दी गई शर्तों के अनुरूप जांच शुरू करके एवं आयोजित करके और इन पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को पहुंचाई जाने वाली आर्थिक क्षति तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन को स्थापित करके, प्राधिकारी का विचार है कि पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति को दूर करने के लिए की जाने वाली जांच पूरी होना लम्बित रहने तक निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना अपेक्षित है। इस मामले के तथ्यपरक मैट्रिक्स और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रमात्रा आधार पर अमरीकी डॉलर में पाटनरोधी शुल्क की संस्तुति करना उपयुक्त माना जाता है। अतः, प्राधिकारी सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर निम्नलिखित स्वरूप

और ढंग से निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना जरूरी समझते हैं और उसका अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं।

109. प्राधिकारी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति दूर की जा सके। तदनुसार, सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के सभी आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को मंजूर किए जाने की स्थिति में, इस अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कालम 9 में निर्धारित राशि के अनुसार निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने की सिफारिश की जाती है।

तालिका

क. सं.	शीर्षक	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	28299010	सोडियम परक्लोरेट	सभी ग्रेड	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	0.23	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
2	28299010	सोडियम परक्लोरेट	सभी ग्रेड	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	0.23	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर

110. इस उद्देश्य के लिए आयातों का उतराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3,3क,8ख,9 और 9क के अंतर्गत उद्गहित शुल्कों के सिवाय सीमाशुल्क संबंधी सभी शुल्क शामिल होंगे।
111. इस आदेश के विरुद्ध अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष दायर की जा सकती है।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th June, 2013
FINAL FINDINGS

Subject : Anti dumping investigation concerning imports of Sodium Perchlorate originating in or exported from China PR

F. No. 14/10/2012-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti - Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the AD Rules);

2. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), under the AD Rules, received a written application from M/s Calibre Chemicals Pvt. Limited alleging dumping of Sodium Perchlorate, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country) and consequent injury to domestic industry and requested for initiation of anti-dumping investigation and levy of anti dumping measures.

3. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

4. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the application containing, *inter alia*, allegations of dumping and consequent injury to the domestic industry before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules.

5. Accordingly, the Authority initiated an investigation into the alleged dumping, and consequent 'injury' to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping measure, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

6. Procedure described below has been followed with regard to this investigation:

- i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Anti-dumping Rules.
- ii. The Authority issued a public notice dated 27th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
- iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicant) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the Anti-dumping Rules.
- iv. The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India (whose details were made available by the Applicant) and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.
- v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-dumping Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- vi. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject country in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:
 - a. Dalian Gaojia Chemical Co., Ltd
 - b. Dalian Tuowei International Trade Co., Ltd
 - c. Changsha Xiang Wei Chemical Trade Co., Ltd.
 - d. Dalian Baobo Commercial Business Co., Ltd
 - e. Tianjin Bairun International Trade Co., Ltd.
 - f. Changsha Xiang Wei Chemical Trade Co., Ltd

- vii. None of the exporters from the subject country has responded to the initiation notification except one exporter M/s Dalian Chlorate Ltd who filed the response very late after the initiation notification. However, the Authority accepted this response. The examination of response of this producer and exporter showed that the response was deficient and accordingly, a deficiency letter was issued to the producer and exporter to submit their reply. As the exporter did not submit the response to the deficiency letter in the form and manner of exporter's questionnaire, the same has not been accepted by the Authority.
- viii. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules:
- a. Indian Explosives limited
 - b. Solar Industries Limited
 - c. Suma Chemical Pvt. Ltd.
- ix. In response to the initiation notification, the following importer has responded:
- a. Suma Chemical Pvt. Ltd.
 - b. Indian Explosives limited
 - c. Solar Industries Limited
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of the subject goods for the past three years, including the period of investigation. The transaction wise import data received from the DGCI&S has been relied upon by the Authority in this finding. There were certain errors in the DGCIS transaction wise data and these have been suitably corrected after taking into account the responses filed by the various interested parties.
- xii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry. The NIP has been determined after onsite verification at the premises of the domestic industry as per Annexure III of the anti dumping rules.
- xiii. The Authority held a public hearing on 01.05.2013 to hear the interested parties orally. The interested parties present at the time of hearing were advised to file

written submissions of the views expressed orally and were also given an opportunity to file rejoinder to the views expressed by other interested parties. The written submissions and rejoinders received from interested parties have been considered, to the extent considered relevant.

- xiv. On the spot verification of the data provided by the applicant was carried out to the extent considered necessary.
- xv. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts were disclosed by the Authority to the known interested parties and comments received on the same, have been considered in the final finding. The following interested parties have submitted their comments to the disclosure statement.
- a. Indian Explosives limited
 - b. Solar Industries Limited
 - c. M/s Calibre Chemicals Pvt. Limited
- xvi. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2011 to 31st March, 2012 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from April 2008-March 2009, April 2009-March 2010, April 2010-March 2011, and the POI.
- xvii. The submissions made by the interested parties considered relevant by the Authority, have been addressed in this final finding.
- xviii. *** in this final findings represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xix. The exchange rate adopted for the POI is 1 US \$ =Rs 48.14

B. Product Under Consideration and Like Article

Views of the Domestic Industry

7. Sodium perchlorate is the inorganic compound with the chemical formula NaClO_4 . It is commercially available as Sodium Perchlorate (Anhydrous) and Sodium Perchlorate (Monohydrate). The Monohydrate contains one molecule of water. It is the most soluble of the common perchlorate salts.
8. Sodium Perchlorate is a white crystalline, hygroscopic solid that is highly soluble in water and in alcohol. It usually comes as the monohydrate, which has a rhombic crystal structure. It is used to manufacture explosives for mining, in perchloric acid and other perchlorates

manufacture and UV Stabilizer for engineering plastics. It is classified in Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 2829 90 and 28299010.

9. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject country are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods.
10. Responding interested party itself has consumed the domestic product and imported product interchangeably. Further, the imported product and domestic product is nothing but Sodium Perchlorate. There is no significant difference in the goods supplied by the domestic industry and goods imported from China
11. There is no basis for the presumption that the petitioner is not producing Anhydrous grade. In fact, petitioner is producing and selling Anhydrous grade.
12. Dumping and injury to the domestic industry are required to be seen for an "article" and not for "each of the type of an article". Further, the Designated Authority can consider exclusion of a product type, only if that product type or like article thereof has not been offered by the domestic industry. The Designated Authority should not consider exclusion of a product type not imported into India. If this test of considering exclusion of product type not imported into India were to be applied, practically, it would imply reducing definition of "article" to "product types" and defining product under consideration as the product types imported only.
13. The fact that one grade is priced higher than another grade is entirely immaterial. The DA has by now conducted numerous investigations where price of one grade is higher than other grade and these have been considered as one article such as caustic soda – lye and flake, phosphoric acid – Technical and Food grade, HR Coils – Plates and sheets. Post disclosure, the domestic industry has reiterated its submissions that there is no difference in Sodium Perchlorate produced by the domestic industry and those imported from subject country and the product under consideration in this investigation is Sodium Perchlorate. In their submission before the Authority they have submitted that they have manufactured and sold Sodium Perchlorate also in anhydrous grade forms and in this regard they have enclosed the copies of invoices which show the sales of sodium perchlorate (anhydrous grade).

View of the Importers/consumers and other interested parties

14. Submissions made by importers/consumers and other interested parties are as follows:
 - a. Imported and domestic products cannot be termed as 'like articles'.

- b. Anhydrous grade must be excluded as the petitioner is not manufacturing and it is not being imported into India. Therefore, there cannot be any injury to the domestic industry on account of anhydrous grade.
- c. There is absence of commercial competition between the two grades due to huge price and cost difference. The price of anhydrous grade is at least 25% higher than the price of monohydrate grade.
- d. Post disclosure M/s Indian explosives Limited has drawn the attention to the Authority towards the imports statistics submitted by domestic industry, where anhydrous grade has been specifically excluded from the scope of PUC. In this regard they have attached various exhibits where the domestic industry has only referred to monohydrate grade i.e. in the import statistics enclosed by the petitioner in their petition, constructed normal value, export price, proforma IVA and B. They have further stated that anhydrous grade is not imported to India and the domestic industry has not provided any injury information relating to anhydrous grade
- e. It has been further submitted by the importer that when the application filed by the domestic industry itself not covers the anhydrous grade, then subsequent inclusion of such grade is not permitted. It has also been submitted that anhydrous grade is not imported into India and domestic industry has not provided any injury information relating to anhydrous grade. Further, it has been submitted by the importer that though the domestic industry has claimed that they are involved in production and sale of anhydrous grade, no evidence has been submitted to substantiate such claim to the other interested parties or the Authority and mere statement in the submission is not sufficient to substantiate the claims. Therefore, they have requested the authority to exclude anhydrous grade from the scope of PUC.

Examination of the Authority

15. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Sodium Perchlorate" from China PR. The main function of sodium perchlorate is to manufacture explosives for mining, in perchloric acid and other perchlorates manufacture and UV Stabilizer for engineering plastics. Sodium perchlorate is an organic compound and is classified under Chapter 28 (within perchlorates with 8 digit subhead 28299010) of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation
16. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."

17. After considering the information on record, the Authority is of the view that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject country are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process, and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. The consumers are using the two interchangeably.
18. Indian Explosive Ltd has contended without any supporting evidence that domestic product is not like article to the imported product. Further, no verifiable evidence has been provided by Indian Explosive Ltd. With regard to the contention of Indian Explosives Ltd that cost and price in a market economy third country is available, it is noted that no such information has been provided by Indian Explosives Ltd. Petitioner claimed that no such information is publically available. The web search also has not shown any such publically available information. The information provided in the petition however shows that the domestic and imported product constitutes one like article.
19. As regards the contention that anhydrous grade must be excluded as the petitioner is not manufacturing and it is not being imported into India, it is noted that the domestic industry is in fact manufacturing anhydrous grade. With regard to submissions from the importer post disclosure, it is stated that the petition clearly stated the PUC as sodium perchlorate. With regard to some of the exhibits enclosed and cited by the importer in their post disclosure statement, it is noted that though some of the exhibits mention the product heading as SPM (Sodium Perchlorate Monohydrate), the subsequent injury information received from the domestic industry included information with respect to Sodium Perchlorate as a whole. Further, the import data shown as one of the exhibits mention Sodium Perchlorate as well as Sodium Perchlorate Monohydrate imported from China PR as PUC. Further, all the injury information as well as determination of non-injurious price for the domestic industry has made for Sodium Perchlorate as a whole. As already mentioned elsewhere in the finding, the domestic industry has placed copies of sales invoice showing Sodium Perchlorate anhydrous grade as well. Thus, from the information placed before the authority, it is noted that the domestic industry is indeed manufacturing both the grades i.e. monohydrates as well as anhydrous grade. Therefore exclusion of the grade from the scope of product under consideration is not warranted. Further, the subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject countries are technically and commercially substitutable. The investigation covers all forms of sodium perchlorate.

C. Domestic Industry and Standing

20. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under: -

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

21. With regard to the argument of Indian Explosive Ltd (IEL) that petitioner is not a domestic company, the Authority notes that the petitioner is a company incorporated in India and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). IEL has not established how the petitioner does not constitute a domestic producer and domestic industry within the meaning of Anti Dumping Rules.
22. After examining the records placed by the various interested parties, it is noted that the Application has been filed by M/s Calibre Chemicals Pvt. Limited, which is the sole manufacturer of the product under consideration. As per the evidence available on record, the petitioner has not imported the product under consideration, nor there exist any other producer of the product under consideration in India. The Authority therefore holds that the petitioner commands a major proportion of the production of the subject goods in India and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b).

D. Confidentiality

Views of the Domestic Industry

23. Submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality are as follows:
 - i. The DA has satisfied itself with regard to confidentiality claimed by the petitioner. It is also pointed out that Rule 7 does not allow the DA to reject any information. All relevant information has been made available to the extent required. The importer is trying to impede the process of investigation.
 - ii. The petitioner has disclosed all that information which was required under the rules. Petitioner is a private limited company and therefore is not obliged to disclose its Annual Report to the interested parties. Yet, petitioner has made available Annual Report for the period 2011-12. Further, petitioner has made available extracts from the Annual Report for the entire injury period.
 - iii. Deductions from export price have been explained in the non-confidential version itself.

View of the Importers/consumers and other interested parties

24. Submissions made by importers/consumers and other interested parties with regard to confidentiality are as follows:

- i. Unwarranted confidentiality claims by the petitioner with respect to (a) source of price considered for sodium chlorate, (b) Annual reports for the injury period and POI, and (c) Deductions from export price in arriving at the ex-factory export price.
- ii. If the petitioner refrains from providing any of the above mentioned information on non confidential basis, the information submitted on confidential basis should also be rejected in line with Rule 7(3) of the AD Rules and the investigation be terminated immediately.
- iii. Authority should not take any action against the interest of the respondent unless a meaningful summary of the above mentioned information is made available to the respondent and an opportunity of being heard by way of fresh public hearing should be granted to the respondent.
- iv. Import statistics obtained from DGCI&S and US Customs data must also be disclosed to the other interested parties.
- v. One of the importers has submitted in his post disclosure comments that non-disclosure of essential information and by claiming excess confidentiality has hindered the respondent from filing a meaningful submission. Following information has not been provided to other interested parties:
 - i. Source of price considered for sodium chlorate
 - ii. Annual reports for the injury period and POI
 - iii. Deductions from export price in arriving at the ex-factory export price
 - iv. Import statistic obtained from DGCI&S

Examination by the Authority

25. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).
26. With regard to confidentiality of information, Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. With regard to non-disclosure of essential information alleged by importer, it is noted that all the information as mentioned in para 24 has already been placed in the public file and in the subject finding. With regard to source of the price considered for Sodium chlorate, it is noted that international price of Sodium chlorate available as per World Trade Atlas has been taken into account for determination of constructed normal value. With regard to annual report of the domestic industry, it is stated that the same has already been put in the public file following public hearing. With regards to deduction from export price to arrive at the ex-factory export price, it is stated that the adjustment has been done on the basis of facts available in this case as none of the exporters have submitted the required information to the Authority in the form and manner of exporters questionnaire. With regard to import statistics obtained from DGCIS, it is noted that the same has been examined under the appropriate heading in this findings.

E. Miscellaneous Submissions

Views of the Domestic Industry

27. Miscellaneous submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. Cost on account of product under consideration forms insignificant part in the Solar Industry's cost. Further, the proposed anti dumping duty shall not have significant adverse effect on the global competitiveness of the company, as imports for exports are permitted without payment of anti-dumping duty.
- ii. Purpose of anti dumping duty is not to restrict imports, it is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- iii. The petition is targeted to address the dumping being faced by the domestic industry. There is no other motive behind the same.
- iv. The petitioner has provided best available information with regard to import data. The information constitutes positive evidence within the meaning of anti dumping law and practice. Further, the Designated Authority has routinely accepted data from secondary sources for the purpose.
- v. The petition was based on data received from M/s. Balaji Data Information Services and a non-confidential version of the same has been disclosed to the interested parties through the petition.

View of the Importers/consumers and other interested parties

28. Miscellaneous submissions made by importers/consumers and other interested parties are as follows:

- i. Petition is motivated to derive narrow profit objective by distorting the accessibility to better quality and price including service of the imported product by domestic manufacturers which contrary to the spirit of international trade and treaties.
- ii. To maintain global competitiveness Solar Industries need to bring their costing to the lowest possible levels. Imports of raw material are the part of strategy to enable them to achieve global competitiveness. Imposition of extra duty on behest of sole producer who will then monopolise the prices is detrimental to the importers interest.
- iii. Transaction wise import statistics has not been disclosed to the other interested parties. The domestic industry should not be allowed to change the basis of the import statistics at the time of the public hearing. The revised data is belated.
- iv. In case authority decides to consider such import statistics, the interested parties should be provided DGCIS data along with a detailed write up about the methodology followed by the petitioner in arriving at the import data.
- v. During the course of the public hearing, DA instructed the petitioner to submit the import statistics procured from DGCI&S & US Customs and place the same in public file. The petitioner has refrained itself from submitting such data, amounting to gross violation to

the instructions of the authority. Therefore the authority should disregard such import statistics. In case the authority decides to consider such import statistics, we request DGAD to kindly provide all the interested parties with the DGCIS data.

Examination by Authority

29. The miscellaneous submissions made by the interested parties have been analysed by the Authority as follows:

- a. As regards the contention that transaction wise import statistics has not been disclosed to the other interested parties, it is noted that the Application Proforma does not require submission of transaction wise import data. Further, it is noted that the domestic industry has analyzed the data procured from Balaji Data Information Services and has disclosed non confidential version of the information based on such data to the interested parties.
- b. As regards the contention that import statistics should not be changed at the time of the public hearing, it is noted that it has been the practice of the Authority to obtain data from the DGCIS during the course of the investigations and examine the same for the purpose of determination. In fact, during the proceedings, the Authority received transaction wise information from DGCIS which was analysed during the investigation. A few discrepancies were noted during the analysis and further investigations were carried out by the Authority to ascertain the source of the imports by contacting the importers of such goods (which was mentioned in the DGCIS transaction wise data). It was claimed by the domestic industry that no subject goods have been imported from USA and UK during period of investigation and they enclosed information from US customs and Euro stat data. It was noted during the examination of DGCIS transaction wise data that out of the three consignments where it was noted that subject goods have been imported from non subject countries, a closer examination of two bills of entries suggested that these subject goods have indeed been imported from subject country only. In one case, the bill of entry no, date as well as volume of subject goods import matched with the importers data while in other case, the date, Qty as well as 6 digits of bill of entry matched with that of cooperating importer. With regards to one consignment of subject goods reflected in DGCIS data to have been imported from UK, it was noted from the importer's reply that they had not imported such goods from UK. Later, it was also confirmed from the responding importer data that the said subject goods are from China PR only.
- c. With regard to making available the transaction wise data of DGCIS in the public file, it is stated that as per the practice of the Authority, the transaction wise data received from DGCIS which mentions bill of entry no, date as well as importers name have not been kept in the public file. However, the culled out data in terms of volume and value including analysis has been mentioned clearly in the final findings.
- d. As regards the contention that imposition of extra duty on behest of sole producer who will then monopolize the prices and the same would be detrimental to the consumers interest, it is noted that anti dumping duties are levied after following the due procedure

established by law and only after the requirements as provided under the law are met and not merely on behest of the domestic producer's claim. Further, the objective of anti dumping duty is to give a level playing field to the domestic industry, imports are not barred as a result of imposition of anti dumping duty.

Normal Value, Export Price And Dumping Margin

30. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. As mentioned in this disclosure statement, M/s Dalian Chlorate responded very late to the initiation notification and submitted response to the exporter's questionnaire much outside the response period. The same, however, was accepted by the Authority for further examination. During the process of examination, it was noted that the same was grossly deficient and accordingly, a deficiency letter was issued to the exporter asking them to attend to the deficiencies within a given time frame. The response which was received after the stipulated period was also deficient. It was noted after examining the response that the information as asked in the questionnaire were not provided in the form and manner of exporter's questionnaire. In particular, basis of the adjustments claimed in their export prices to India was not mentioned. In fact, some of the significant adjustments like inland freight, basis of overseas freight has not been mentioned. In addition, it is noted that Appendix 2A in the form and manner of exporter's questionnaire has not been provided. Further, the exports to India in terms of volumes and values differ in the Appendix 2 and 3 given by them. Responses to other appendix as per the exporter's questionnaire have not been provided by the exporter. Further, no evidence of the payment received from the Indian importer was enclosed. In view of the above fact, it is proposed not to accept the deficient response of the exporter and not to grant individual dumping margin to that exporter. Apart from this exporter, none of the producer/exporter from China PR has co-operated in this investigation by filing their Questionnaires' responses. **Post disclosure**, M/s Dalian Chlorate Ltd has submitted that their response has been incorrectly rejected by the Authority as they were only exporter to have filed the response. The matter has been examined and it is noted that M/s Dalian Chlorate Ltd has failed to submit the response in the form and manner of exporter's questionnaire and therefore, their response has not been accepted by the Authority.

Views of the Domestic Industry

31. The domestic industry has stated as follows:

- a. It has been contended by the domestic industry that China PR should be treated as non-market economy country, *inter alia*, stating that:
 - Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity – It has been contended by the Domestic industry that the European Commission has consistently held that possibilities of State interference cannot be ruled out in cases, where there is significant share of a State owned /controlled entity. It has been contended that it is not only the question of past

interferences alone, but also possibilities of potential State interference in the future after the imposition of anti dumping duties that is relevant for granting market economy treatment.

- Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values: It has been contended by the Domestic industry that “substantially reflect market values” has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market. The Domestic Industry contends that the fact that such prices are comparable to the price prevailing in China PR is grossly insufficient.
- Major inputs include utilities: It has been contended by the Domestic industry that production of the products concerned require power and fuel as a major item of utility. Admittedly, while the power supplier is a State owned entity, insufficient information is available with regard to fuel supplier. It has not been established by the exporters that the price of utilities reflect fair market values.
- Market economy status cannot be given unless the responding exporters establish that their books are audited in line with international accounting standards: It has been contended by the Domestic industry that Chinese exporters have repeatedly disputed the treatment of European Commission to reject market economy treatment in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with Chinese GAAP. Chinese companies in such cases have been contending that the requirement of insisting on compliance with International Accounting Standards is beyond law. The European Commission has held that the requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report. To quote the European Commission, reliability of the accounts is not established with regard to this aspect unless the books are consistent with International Accounting Standards.
- Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied: It has been contended by the Domestic industry that the European Commission has repeatedly insisted that market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the Rules.
- Onus/obligations: It has been contended by the Domestic industry that it is not for the Authority to establish that the responding companies are indeed operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment. On the contrary, it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
- Transformation: It has been contended by the Domestic industry that in a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.
- It has been contended by the Domestic industry that failure to satisfy a number of conditions mentioned above by the responding Chinese exporters, is sufficient to hold

that market economy status cannot be granted to responding Chinese companies and thus the Normal value should be determined in accordance with Para-7 of the Rules.

- b. Domestic industry has further stated that none of the Chinese producers has claimed market economy treatment. Thus, the Authority cannot consider whether one or more Chinese company relating to the product under consideration or the Chinese economy relating to the product under consideration may be accorded market economy treatment in the present case.
- c. The raw material is sodium chlorate and the same has been adopted for the purpose of determining normal value. In case of non market economy, the Authority is required to consider cost or price in a market economy third country.
- d. No submissions should be considered on behalf of the Dalian Chlorate Company for the reason that the company has not filed questionnaire response and submissions within time limits. In fact, company has not made any oral submissions at the time of oral hearing. M/s. Dua Associates clearly stated at the time of hearing that they were representing Solar Industries Ltd.
- e. The Chinese exporters have not cooperated with the Authority and have not established difference in manufacturing process and impact thereof. An importer in India cannot establish the existence of different manufacturing process between petitioner and foreign producer nor an importer can quantify the impact of the same as is evident in the matter of *AIIGMA v. Designated Authority* - 2000 (119) E.L.T. 333 (Tri.) decided by the Hon'ble CESTAT.
- f. Importer cannot provide information with regard to normal value and the importers or consumers in India are not entitled to question the correctness or otherwise of the normal value.
- g. The Designated Authority is required to determine normal value for the like article. The domestic industry has produced and sold like article and, therefore, the Designated Authority is required to consider the normal value based on Annexure-7 to the rules.
- h. Once the Designated Authority comes to a conclusion that Para 7 shall apply, the DA is not required to consider Chinese cost. The same becomes entirely irrelevant.
- i. Petitioner has made claim based on verifiable information. The Designated Authority has since conducted verification and may, therefore, consider facts on basis of verified data. Confidentiality of evidence is protected under Rule 7 and the same cannot be disclosed to other interested parties.
- j. The petitioner has provided information based on its own experience. The raw material for petitioner is sodium chlorate and the same has been adopted for the purpose of determining normal value. In case of non market economy, the Designated Authority is required to consider cost or price in a market economy third country.
- k. The company has adopted either production or turnover ratio for allocation and apportionment of fixed expenses. As a result of reduction in production, the company has charged lower share of expenses and therefore the cost of production in POI is not higher on account of lower production.
- l. The share of expenditure charged to the product in the past was higher than the share of expenditure charged in the POI. This is on account of reduction in production. Thus, as a result of reduction in production, the company has charged lower share of expenses and therefore the cost of production in POI is not higher on account of lower production.

- m. The Designated Authority does not consider actual conversion cost and instead adopts normated conversion cost for the purpose of determination of normal value. Such being the case, in any case, there is no basis for the argument that the constructed normal value may be inflated.
- n. They have requested the authority to reject the exporter questionnaire response from M/s Dalian Chlorate Ltd.

View of the Importers/consumers and other interested parties

32. Submissions made by importers/consumers and other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. For the determination of normal value of the product 'market' and 'non-market-economy' are not relevant and carry no bearing.
- ii. The cost or price in a market economy third country is available and has not been provided.
- iii. Domestic Industry has wrongly constructed the normal value. The CNV cannot be as high as 1.97 USD.
- iv. Source of data from Balaji Data Information Services after adjustment is not authentic and reliable
- v. Evidences have not been provided to show that normal value is higher than the net export price.
- vi. There is difference in manufacturing process of the petitioner and Chinese manufacturers. Petitioner manufactures using sodium chlorate as raw material and converting the same into Sodium Perchlorate. Whereas the manufacturers in China PR manufacture the subject goods by converting common salt plus water into sodium chlorate and sodium chlorate into Sodium Perchlorate. The cost of production of the petitioner should be adjusted accordingly.
- vii. All conversion costs including power costs, SGA expenses, etc. have been determined based on the domestic industry's cost sheet. The power cost in China is not the same as the power cost in India.
- viii. The cost of conversion cannot be as high as submitted by the petitioner.
- ix. Dumping margin is unsubstantiated, as evidences for arriving at normal value and ex-factory export price have not been made available to the Authority.
- x. Construction of the Normal Value is flawed and needs be revisited by the Designated Authority. Constructed normal value has been artificially and intentionally inflated by the Domestic Industry. Perhaps the Constructed Normal Value of Rs. 92.27 per Kg calculated by the Domestic Industry is on account of abnormally high Cost of Production in the POI i.e. 40% capacity utilization.

Examination of Market Economy claims in respect of China PR by the Authority

33. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters/producers in terms of the AD Rules.
34. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy may be rebutted, if the exporter(s) /producer(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether: -
- the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
 - the exchange rate conversions are carried out at the market rate.
35. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority, none of Chinese producers/exporters has submitted the questionnaires' responses including the market economy questionnaire's response as per the form and manner of it and sought to rebut the non-market economy presumption.

Determination of Normal value in respect of Exporters / Producers from China PR

36. As none of Chinese producers and exporters has submitted the questionnaires' responses; the Authority has estimated the Normal value in China PR on the basis of Para-7 to Annexure-I to the AD Rules. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides as follows.

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or

where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments”.

37. The Authority had stated, in the initiation notification that the applicant has claimed that China PR should be treated as Non Market Economy and therefore Normal value in case of China PR should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annex-I of the AD Rules. The applicant has submitted that India can be considered as an appropriate market economy third country for determination of Normal value in China PR, pleading that information for market economy third country is not available to them. This claim has not been contested by any other interested party.
38. Considering that there has been no response from any exporter/producer of the subject goods from China PR and further noting that information/data regarding appropriate market economy third country for determination of Normal value in China PR is not available on record; the Authority has determined the Normal value for China PR on available ‘reasonable basis’, in terms of second proviso of para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration has been determined based on constructed costs of production, duly adjusted. The Normal Value has been constructed as per the methodology described below:

Methodology adopted for constructing Normal Value in case of China PR

39. The Authority has constructed Normal value for the Chinese producers on the following basis –
- a. Prices of major inputs have been considered on the basis of prevailing international price.
 - b. Consumption of raw materials per unit of production and the conversion costs have been considered on the basis of best information/data available on record, i.e., on the basis of information/data of the domestic industry. As regards the contention that the cost of production of the petitioner should be adjusted as per the raw material usage by the Chinese producers, it is noted that the response submitted by the Chinese producers have not been accepted and therefore normal value cannot be adopted based on Chinese data. The Authority has considered best information/data available on record as mandated under the Anti dumping Rules, i.e., on the basis of information/data of the domestic industry. Further, the authority has not adopted actual cost of production of the petitioner for determining normal value. The authority has considered normatted cost of production as adopted for the purpose of non injurious price for determining normal value in China.

- c. Selling, general & administrative costs have been taken on the basis of best information/data available on record, that is, on the basis of information/data of the domestic industry.
- d. Profit has been taken @ 5% of ex-factory costs, excluding interest.
40. With regard to the contention of Indian Explosives Ltd that cost and price in a market economy third country is available, it is noted that no such information has been provided by Indian Explosives Ltd. Petitioner claimed that no such information is publically available. The web search also has not shown any such publically available information.
41. With regard to the argument of Solar Industries that the normal value constructed is flawed, the Authority notes that the calculation of normal value is based on positive evidence. Further, it has been assumed without any basis that Sodium Chlorate alone constitutes a major part of the cost.
42. Normal value of the product under consideration has been determined as Rs *** per kg /US\$ *** per kg.

EXPORT PRICE

43. Since, no response in the form and manner of exporter's questionnaire has been received from any producer/exporter of the subject goods from China PR; the Authority has determined Export Price as per 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. For this purpose, the volume of imports as per DGCI&S data has been relied upon. The adjustments to the CIF prices have been made as per facts available on record. Accordingly, export price has been adjusted for ocean freight, port expenses in China, inland freight, marine insurance and bank commission.
44. Indian Explosives Ltd has disputed adoption of secondary source data in the petition. While the authority notes that the petitioner is justified in adopting best available information, in any case, the present determination is based on DGCI&S information.

DUMPING MARGIN

45. Considering the Normal value and Export price as determined above, the dumping margin has been determined as follows. It is seen that the dumping margin is more than de-minimus and significant.

Particulars	Rs/Kg	US\$/Kg
-------------	-------	---------

Normal value	***	***
Net Export price	***	***
Dumping Margin	***	***
Dumping Margin (%)	***	***
Dumping Margin (%) Range	20-30	20-30

F. Injury Determination

Views of the Domestic Industry

46. The submissions made by domestic industry with regard to injury and casual link are as follows:
- The volume of imports has shown massive increase in absolute terms.
 - Demand for the product under consideration has increased significantly over the period of injury, whereas the sales of the domestic have declined significantly even with the enhancement of the capacity.
 - Market share of dumped Chinese imports have increased consistently throughout the period of injury and is very significant in the POI. At the same time the market share of the petitioner has declined.
 - Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry to a significant extent.
 - Imports are depressing the prices of the Domestic Industry and preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumping.
 - Performance of the Domestic Industry has steeply deteriorated in terms of production, capacity utilization, domestic sales, inventories, market share, profits, return on investments, cash flow, and has reached negative levels.
 - There being no other supplier of the product under consideration in the country, decline in the market share, production, sales and capacity utilization and increase in inventories is clearly on account of dumped imports into the country.
 - The factors affecting the prices of the domestic industry are import price from China and input prices. Thus, the price depression and suppression is due to dumping of the product in the market.

- i. Growth of the domestic industry is adverse in terms of both volume and price parameters.
- j. Domestic Industry was capable of meeting substantial part of the Indian demand. The increase in imports cannot be justified by the lack of capacities with the domestic industry.
- k. Imposition of the anti-dumping measures does not prevent or restrict the imports of the subject goods. The intent of the anti-dumping measures is to create a level playing field for the domestic producers vis-a-vis the dumped imports.
- l. There was no adverse volume effect till 2010-11 despite capacity addition and the capacity utilization itself establishes adverse volume effect.
- m. Decline in performance of the domestic industry in POI as compared to previous years clearly implies injury.
- n. Decline in profits, production, sales, capacity utilization in POI and increase in inventories with increase in imports clearly establishes injury.
- o. The law does not require a gradual decline in performance over the injury period. If the performance of the domestic industry declined in POI, the same implies injury.
- p. Performance of the domestic industry shall show deterioration even if interest expenses and depreciation costs are taken at the same level.
- q. With the significant increase in interest costs and depreciation cost in 2009-10, the profitability of the domestic industry was almost maintained. With the decline in interest cost in POI, the profitability steeply deteriorated to a situation of financial losses.
- r. When existing capacities itself remained unutilized, injury to the domestic industry could not have been due to inability of the domestic industry to match up the demand with rise in capacities.
- s. Exports by the petitioner have not declined. There was one time higher exports in 2010-11. Once these exports are excluded, it would be seen that exports in the remaining period have remained at similar level. In any case, if production, sales, capacity utilization, profits, return on investment, cash flow etc. are determined after segregating exports, the data nevertheless shows significant deterioration.
- t. Rules require the Designated Authority to segregate injury caused to the domestic industry due to other factors. Therefore, if it is considered that export performance has impacted the injury analysis, the Designated Authority can consider export performance after segregating exports information.
- u. CESTAT decision Indian Spinners Association vs. Designated Authority 2004 (170) E.L.T. 144 (Tri. - Del.) was entirely different and the same cannot be applied in the present case. Significant decline in profitability over the period clearly establishes injury. Further, injury to the domestic industry is established in terms of decline in production, sales, capacity utilization, profit, return on investment, cash flow.
- v. Opening stocks reported by the petitioner has typographical error. The opening stock of the company was 36 MT, whereas the company has reported opening stock as NIL.

- w. There is a typographical error in the depreciation figure for 2008-09. The corrected figure shows that depreciation charged for the product under consideration has in fact declined.
- x. It is not understood how inability of the domestic industry to meet the demand will lead to injury. The performance of the domestic industry on account of production, domestic sales and capacity utilization would not have deteriorated due to its inability to meet the demand. The performance of the domestic industry would have at the least improved on these accounts in a situation where the domestic industry is not able to meet the demand in the Country.
- y. It cannot be said that the small size industry does not have right to seek protection under dumping law. Moreover, the overall market size for the product is more than Rs. 16 crores.
- z. The purpose of anti dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- aa. No grounds have been made out for termination of the investigations. The product constitutes an insignificant proportion in the consumer's overall business.
- bb. Product under consideration is produced only in India, China, US and Germany. Should the domestic industry not be protected at this stage, the domestic industry will decline further and the petitioner shall be eventually forced to exit from the product. The law has been created to protect legitimate interests of the domestic industry.
- cc. It is well established practice of the Authority to call for DGCI&S data. Even if the petitioner's data based on DGCI&S is not considered, the Designated Authority would follow its own process of calling DGCI&S data and relying on the same. It is also relevant to point out that quality and quantity of evidence improves as an investigation progresses. It is relevant to point out in this regard to the WTO decision in the matter of Panel Report in the matter of Guatemala – definitive anti-dumping measures on grey portland cement from Mexico WT/DS156/R.
- dd. The petitioner is capable of meeting the Indian demand. Imports have not increased due to possible inability of the domestic industry to meet the demand of the product in the Country. Imports have increased due to significant price difference between the domestic price and imported product price.
- ee. Inability of the domestic industry to meet the Indian demand cannot prevent the petitioner from seeking relief against dumped imports. The domestic industry suffered significant decline in capacity utilization from the base year. When existing capacities itself remained unutilized, injury to the domestic industry could not have been due to inability of the domestic industry to match up the demand with rise in capacities.
- ff. Information on shutdown hours and inventories with the domestic industry, clearly establish that the domestic industry sales volumes have suffered because of lack of orders from the domestic market. The domestic industry could have

easily supplied the material from inventories or by utilizing the unutilized capacities.

gg. It is presumptive on the part of importer that the capacity expansion was for export markets. In fact, the domestic industry is predominantly in domestic market. In any case, the domestic industry suffered loss of production and was faced with rising inventories.

hh. The company did not suffer so significant injury earlier as the company is now suffering. Because the company did not take action at that point in time does not mean that the company is now prevented from taking action.

ii. Post disclosure, they have reiterated their submissions on injury and causal link. On the issue of import data, they have denied the fact that changes were made in the petition without giving an opportunity to interested parties to comment and cost of production of the domestic industry is very high because of lower production. They have again denied the submissions made by the importers that they are unable to support the domestic demand of the subject goods. The domestic industry has requested in his post disclosure comments to impose anti-dumping duties on fixed quantum basis. They have cited the reasons for imposition of fixed duty as possible circumvention of anti-dumping duty, lack of mechanisms by the custom port authorities to ensure correctness of import price reported by an importer and significant changes in the cost of production of the product with changes in the cost of inputs. They have also requested that the anti-dumping duty to be imposed in US \$ citing the fact that rupee has depreciated significantly.

View of the Importers/consumers and other interested parties

47. Submissions made by importers/consumers and other interested parties with regard to injury to the domestic industry are as follows:

- i. Domestic industry has not suffered any injury on account of the imports of subject goods.
- ii. Domestic industry is not capable enough to cater the domestic demand.
- iii. Domestic industry was able to achieve 88% of capacity utilization, irrespective of inflow of imports and newly added capacities until 2010-11. It is only in the POI wherein the capacity utilization decline. Injury needs to be shown over the span of the injury period hence there is no causal link between imports and injury.
- iv. Profits of the domestic industry were increasing till the year 2010-11, inspite of gradual increase in imports from subject countries. This clearly shows absence of causal link between imports and injury.
- v. Domestic industry's interest cost has increased substantially in the POI despite increase in capacity utilization. It appears that capacity expansion has largely been

- funded by debt having a bearing on increasing cost of production per MT which can not be linked with the imports.
- vi. Domestic industry's depreciation cost is 142% higher in the POI compared with the base year 2008-09 having a positive bearing on cost of production which cannot be linked with the imports. Sudden decrease on depreciation indicates disposal of physical assets which needs to be examined.
 - vii. Domestic industry has not increased its capacity in proportion to the increase in total demand the domestic market. It increased its capacity with 25% whereas demand increased by 65%.
 - viii. Domestic industry profits declined in the year 2009-10 when the landed imports were priced highest at Rs 66.54.
 - ix. It is the fall in the export demand that is hurting the petitioner the most during POI. Imports cannot be blamed for fall in capacity utilization because of fall in exports.
 - x. It was only during POI that there was a loss and a negative ROCE. One cannot take the loss alleged to have been suffered during the POI alone to come to a conclusion that the domestic industry has suffered material injury. Reference to decision of CESTAT in the matter of Indian Spinners Association vs. Designated Authority 2004 (170) E.L.T. 144 (Tri. - Del.).
 - xi. During 2008-09, the production of the petitioner was 1288 MT, whereas the sales during the same period were 1319 MT. However, it can be seen that opening stock of the petitioner during 2008-09 was nil.
 - xii. No correlation between capacity, depreciation and Net Fixed Assets.
 - xiii. Causal link is missing. The domestic industry has failed to provide evidence to show that such lower priced imports actually caused injury to them. The main reason for the injury to the domestic industry is their inability to cater the needs of the user at the time of high demand.
 - xiv. The overall value of the industry in India is not more than Rs.6.50 crores to Rs.7.00 crores. Considering the miniscule size of the market, DGAD should consider whether it is worthwhile to impose a protective measure in such minor products also.
 - xv. The injury to the petitioner is due to dismal export performance and very poor performance of the other products produced and sold by the petitioner.
 - xvi. The effects of injury are not demonstrated in terms of the parameters set out in paragraph (iv) of the Annexure II of the rules made in this behalf.
 - xvii. Domestic Industry has not only changed data with respect to imports but has also made amendments to its own data in the paper book.
 - xviii. The Domestic Industry is unable to support the domestic demand of the subject goods thus warranting the import of the subject goods. During the Period of Investigation the domestic demand was 2042 MT whereas, the domestic

- production decreased to 804 MT. Since the domestic industry is a monopolist, this gap in demand and supply could only be bridged by imports from subject country.
- xix. The focus of the domestic industry has been on export sales. The reason for the focus of the domestic industry on export sales is high returns on investment as opposed to domestic sales.
- xx. Domestic Industry included additional capacities in the year 2010-11, however the same was to cater to the export market and not the domestic market. In the year 2010-11 the export sales was increased from 392 MT to 760 MT. Thus, it is quite clear that the Domestic Industry added capacity to cater to the export sales and not domestic sales and cannot now claim injury on account of loss of market share due to increase in imports from China.
- xxi. The surge of imports was in the year 2009-10, when the subject imports increased from 216 MT to 1234 MT. Why the instant petition was not filed for the year 2009-10 and was filed when the quantum of imports from subject countries remained more or less the same.
- xxii. Along with 48% decline in Domestic Sales the Domestic Industry has also suffered 163% decline in its Exports Sales. The loss of profit due to decrease in exports sales can in no way be attributable to imports of subject goods.
- xxiii. Import quantity as reported by the petitioner is different in all the submissions made by the petitioner.
- xxiv. One cannot take the loss alleged to have been suffered during the POI alone to come to a conclusion that the domestic industry has suffered material injury.
- xxv. Post disclosure, one of the importers has requested the Authority to adjust cost of production of the petitioner by taking the appropriate cost of conversion of common salt and water into sodium chlorate for the purpose of determination of NIP.
- xxvi. Post disclosure, one of the importer has submitted that the domestic industry is suffering injury because of own reasons and dumping has no relation to the injury caused to the domestic industry. Further, it has been stated that the domestic industry is a monopolist and imposition of ADD would lead to undue benefit to the domestic industry. They have requested the Authority to impose ADD on reference price basis.

Examination by the Authority

48. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on injury to the domestic industry and has analyzed injury to the domestic industry considering the facts available on record and applicable law as follows. The submissions made by the interested parties have been considered to the extent found pertinent and have been examined below and in the relevant sections of these findings.

49. As regards the argument that considering the miniscule size of the market, Authority should consider whether it is worthwhile to impose a protective measure in such minor products, it is noted that the anti dumping duty levied is to eliminate unfair trade practices and to provide the domestic industry a fair opportunity to compete in the market. Antidumping law does not distinguish the domestic industry on account of its market size and turnover. The right to seek protection under antidumping law cannot be curtailed on such grounds.
50. As regards the argument that the injury to the domestic industry is on account of deterioration in export performance, it is noted that the finding is based on the performance of the domestic industry in the domestic market alone. Performance in the export market has been excluded. The analysis of the injury parameters shows that the imports have increased significantly during the injury period. It is also noted that performance of the domestic industry in exports was almost similar over the injury period, except for 2010-11, when the exports were high. Further, price parameters of the domestic industry deteriorated in 2010-11, when exports were higher. It is thus not established that the claimed injury to the domestic industry is because of exports performance.
51. As regards the argument that the Domestic Industry added capacity to cater to the export sales in 2010-11, it is noted that the domestic industry has significant unutilized capacities. The domestic industry could have produced and sold significantly higher volumes in the domestic market even after the present exports made by the company.
52. As regards the argument that the Domestic Industry is unable to support the domestic demand of the subject goods, it is noted that the domestic industry can meet almost the entire Indian demand. Further, anti dumping measure is not an instrument to restrict imports but to permit the same by providing a level playing field to both the subject exporters and the Domestic Industry. With regard to request of the importer to adjust cost of production of the petitioner by taking the appropriate cost of conversion of common salt and water into sodium chlorate for the purpose of determination of NIP, it is noted that NIP has been determined as per the Annexure III of the anti dumping rules.
53. Rule 11 of the AD Rules read with its Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

54. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules.
55. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
56. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry. Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

57. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

Demand and market share

58. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of domestic industry and other Indian producer have been added to the total imports into India and the same has been summarized below:

SN	Particulars	Units	2008-09	2009-10	2010-11	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	1,023	770	872	481
2	Subject country-Imports	MT	628	1159	1244	1427
3	Total demand/consumption	MT	1,651	1,929	2,116	1,908

59. It is noted that the demand has shown a positive trend throughout the injury period.
60. Indian Explosive has contended that the domestic industry is not capable of meeting the Indian demand. It is however noted that the domestic industry can meet substantial part of the domestic demand. In any case, inability of the domestic industry to meet the domestic demand cannot prevent the domestic industry from seeking protection under the Rules, as the purpose of anti dumping duty is not to restrict imports but to allow the same at prices which will not cause injury to the domestic industry.

G. Volume Effects of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

61. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCIS. The volume of imports of the subject good from the subject country have been analyzed as under:

SN	Particulars	Units	2008-09	2009-10	2010-11	POI
1	Total Imports	MT	628	1,159	1,244	1,427
2	China	MT	628	1,159	1,244	1,427
3	Market Share in Demand					
4	Sales of Domestic Industry	%	61.97	39.92	41.21	25.21
5	Subject country	%	38.03	60.08	58.79	74.79
6	Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Chinese import in relation to production	%	48.76	99.40	70.80	177.49

62. It is noted that:

- i. Imports have increased in absolute terms from 628 MT in base year to 1,427 MT in POI, showing an increase of 127% over the injury period. The increase is considered significant and material.
- ii. While the demand for subject goods increased by about 16% in POI as compared to base year, the volume of imports from subject country increased by about 127% during the corresponding period. The increase in imports in absolute terms is disproportionately higher than the increase in demand of the product in the Country.

- iii. Imports of subject goods from the subject country have increased in relation to the production of the subject good in India, showing 129% increase over the injury period.
 - iv. The market share of the subject country in demand of the product in India has increased, whereas the market share of the domestic industry has declined, despite domestic industry being the sole producer of the subject goods in the domestic market. Market share of China PR increased from 38% in base year to 75% in POI, showing 37% increase over the injury period.
63. It is thus noted that the imports of the product under consideration have increased in absolute terms as also in relation to production and consumption of the product in the Country. It is thus noted that the imports from subject country show significant adverse volume effect.

H. Price effect of imports

64. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

Price undercutting

65. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. Authority has determined net sales realization considering selling price, excluding taxes & duties, rebates, discounts & commissions. Entire domestic sales volumes of the domestic industry have been included in the calculations. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. The comparison was done between net sales realization and landed price of imports. The Authority has determined price undercutting by the dumped imports.
66. The Authority notes that from 2009-10 onwards, the landed prices of the subject goods are significantly below the selling price of the domestic industry which suggests significant price undercutting being caused by the imports of subject goods from subject country as apparent from the following table.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (POI)
Landed price of imports	Rs./KG	71.26	61.07	59.03	62.81
Net Selling Price	Rs./KG	***	***	***	***
Index		100	112	107	103
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%) Range		0-10	20-30	20-30	10-20

67. The Authority notes that the landed price of subject imports of the subject goods are significantly below the selling prices of the domestic industry, resulting in significant price undercutting.

Price-underselling

68. From the table given below, the Authority notes that there is positive price underselling effect:

Country/exporter	Unit	China
Landed Price	Rs./kg	62.81
Non Injurious Price	Rs./kg	***
Price underselling amount	Rs./kg	***
Price underselling %	%	***
Price underselling % Range		10-20

Price suppression/depression

69. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a

significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. Table below shows the factual position.

SN	Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
1	Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
	Index		100	108	102	121
2	Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
	Index		100	112	107	103

70. It is seen that there was increase in both cost of sales as well as selling price over the period (barring 2010-11). However, the increase in selling price was lower as compared to the increase in the costs. It is thus seen that the domestic industry has not been able to increase its selling price commensurate with increase in the cost of sales. It is thus seen that the effect of dumped imports was to prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

I. Economic parameters of the domestic industry

71. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
72. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

i. Production, capacity and capacity utilization of the Domestic Industry

Situation of the domestic industry with regard to production, capacity and capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Installed capacity	MT	1,600	1,600	2,000	2,000
Production	MT	1,288	1,166	1,757	804
Capacity Utilization	%	80%	73%	88%	40%
Domestic Sales	MT	1,023	770	872	481
Total Demand	MT	1,651	1,929	2,116	1,908

73. The Authority notes that sales of the domestic industry declined significantly from 1023 MT to 481 MT whereas the demand for the product under consideration increased from 1651 MT to 1908 MT over the period. Thus, the sales of the domestic industry declined by 53% when demand for the product under consideration increased by 16%. This is in a situation when the domestic industry is the sole producer of the subject goods in the country. The Authority also notes that the low capacity utilization is not only on account of the decrease in domestic sales but also on account of declined in exports.
74. The domestic industry has contended that it has increased its capacity so that it is able to cater the growing demand. However, it is noted that capacity utilization declined from 80% in the base year to 40% in the POI showing a 50% decline.
75. Production of the domestic industry declined from 1288 MT (2008-09) to 804 MT (POI) thus showing about 38% decline over the period. Further, it is noted that the production had increased to 1757 MT in 2010-11 and then declined to 804 MT, thus showing a decline of 54% decline in POI as compared to 2010-11.

ii. Market share:

76. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market shares of the domestic industry have been examined as below:

Demand	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Market Share in Demand					
Domestic Industry	%	61.97	39.92	41.21	25.21
Subject country	%	38.03	60.08	58.79	74.79
Total	%	100	100	100	100

77. It is noted that market share of the domestic industry declined over the injury period, whereas the market share of Chinese imports have shown a significant increase. The market share of the domestic industry shows a decline of about 37% during POI as compared to the base year.
78. It has been contended that domestic industry failed to match up its capacity with the increase in demand and decrease in market share is due to their incapability to match up the same. Comparison of capacity with the domestic industry and enhancement in the capacity with the growth in demand, however, shows that the capacity additions by the domestic industry were in line with present and potential demand for the product in the country. It is not established that decline in market share is due to inability of the domestic industry to produce and sell the product. It is also noted that the domestic industry faced significant decline in capacity utilization & sales volumes.

iii. Profits, return on investment and cash flow

79. The cost of sales, selling price and profit/loss of the domestic industry has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Index		100	108	102	121
Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
Index		100	112	107	103
Profit/Loss	Rs./Kg	***	***	***	***
Index		100	168	167	(105)
Profit/Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Index		100	127	143	(49)
Profit before Interest and Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
Index		100	102	107	(3)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***

Index		100	91	94	5
Capital employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Index		100	175	150	124
Return on investment	%	***	***	***	***
Index		100	59	72	(2)

80. It is noted that the profits of the domestic industry increased upto 2010-2011 and thereafter have shown a significant decline during POI. It is also noted that whereas cost of sales increased during the POI, selling price declined in the POI as compared to the previous year during the corresponding period. Resultantly, profitability of the domestic industry declined significantly and the domestic industry suffered financial losses in the POI.
81. As a result of decline in profits, the return on investment and cash profits declined significantly over the injury period. Return on investment and cash profits of the domestic industry declined to such an extent that the domestic industry suffered negative return on investment in the POI.
82. Interested parties have argued that petitioner has not suffered losses or financial injury. The Authority, however, notes that the verified information concerning cost of production, selling price and profit & loss of the domestic industry shows that the domestic industry has suffered financial losses.
83. As regards the argument that decline in profits is due to increase in depreciation and interest cost, it is noted that there is no abnormal increase in cost on account of interest and depreciation. During the process of investigation, it was noted that there was a typographical error in the amount of depreciation reported in injury statement. It is also noted that profit before interest and depreciation has also shown decline which clearly establishes that the decline in profits is not due to increase in depreciation and interest cost.

iv. Inventories:-

84. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

SN	Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
1	Opening stock	MT	***	***	***	***

2	Closing Stock	MT	***	***	***	***
3	Average Stock	MT	21	7	72	121

85. It is noted that inventories with the Domestic Industry shows significant increase with the increase in the volume of dumped imports. Inventories with the domestic industry are significant in the POI even when the demand for the subject goods has increased. Further, increase in inventories is despite decline in production.

v. Employment and wages

86. The position with regard to employment and wages is as follows:

Company as whole

SN	Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
1	Number of employees	No.	***	***	***	***
	Index		100	142	182	182
2	Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Index		100.00	181.79	273.56	500.94

87. Since the domestic industry does not have dedicated employment for the product under consideration, situation of the domestic industry with regard to employment and wages paid by the domestic industry was examined by considering information for the company for all operations. It is noted that both employment and wages show increase over the period.

vi. Productivity

88. Data relating to productivity shows as follows:

SN	Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
1	Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Index		100	75	125	50

89. It is noted that productivity in terms of production per day has declined in the POI as compared to base year as well as previous year. The decline in productivity could be attributed to decline in production as a result of dumping of the product under consideration.

vii. Magnitude of Dumping

90. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject countries are above de minimis and significant.

viii. Factors affecting domestic prices

91. Consideration of the import prices from China, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market show that the landed value of imported material from China is significantly below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. The benchmark for the domestic industry is the import prices from subject country. There are negligible imports of the product under consideration from other countries. There is no viable substitute to this product. Demand for the product was showing significant increase and could not have been a factor responsible for price suppression faced by the domestic industry. It is thus evident that the only factors responsible for the domestic industry prices are the import prices of the product from China PR and the cost of production of the domestic industry. As the information shows, whereas the cost of production increased, the import prices much lower than the domestic prices prevented the domestic industry from increasing their prices in line with the increase in the cost.

ix. Growth

92. There has been significant growth in the import volumes of the subject goods from the subject country. The growth of the domestic industry in terms of sales and production was negative. Similarly, growth of the domestic industry in respect of profits, cash profit, and return on investment was also negative. Despite significant increase in demand and the domestic industry being the sole producer of the subject goods, the domestic industry is facing negative growth.

J. Conclusion on material injury

93. It is concluded that the dumped imports of the subject goods from the subject country have increased significantly in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India. Imports of the subject goods from subject country are significantly undercutting the prices of domestic industry. The imports are causing significant price suppression. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is concluded that the performance of the domestic industry has deteriorated in respect of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profit, cash flow, return on investment, productivity and inventories, which is significant and material. Thus the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

K. Other Known Factors & Causal Link

94. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows:-

(a) Volume and prices of imports from third countries

95. There are no imports from of product under consideration from other countries. Imports from other countries have also caused injury to the Domestic Industry.

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

96. There has been a constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period. Possible decline in demand is not as a possible reason of injury to the Domestic Industry.

(c) Developments in technology:

97. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology is not a factor causing injury to the domestic injury.

(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

98. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry

(e) Export performance of the domestic industry

99. The injury information provided to the Authority is for domestic operations and therefore possible decline in exports volume could not have caused claimed injury to the Domestic Industry

(f) Productivity of the Domestic Industry

100. It is noted that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee has declined over the period as a result of decline in production. The decline in production is due to increase in the imports of the product in the Country.
101. Indian Explosives Ltd disputed the claim of the petitioner that factors other than imports from China PR are not responsible for injury to the domestic industry. It is, however, noted that IEL has not given any evidence in support of their claim that factors other than dumped imports have also caused injury. Further, the investigation has not shown existence of any significant factor other than dumped imports which could have caused injury to the domestic industry.
102. It is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:
- a) The volume of dumped imports from the subject country increased sharply resulting in increase in the share of dumped imports in demand of the product in India. Consequently, the domestic industry lost its market share.
 - b) The imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry was not able to increase its prices in line with the increase in the costs. Imports were thus resulting in price suppression being faced by the domestic industry.
 - c) Imports of the product under consideration were undercutting the domestic prices, as a result of which the volume of imports increased. Resultantly, the domestic industry faced decline in production, capacity utilization and sales volumes.
 - d) Performance of the domestic industry with regard to profits, cash flow and return on investments deteriorated. Thus, dumping of the product has led to deterioration in performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow and return on investments.
 - e) The domestic industry is faced with significant increase in inventories.

103. It is therefore, concluded that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports of subject goods from subject country.

L. Magnitude of Injury and Injury Margin

Injury Margin

104. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry determined has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during POI. The injury margin determined are as under:-

	Rs/kg	USD/kg
Non injurious price	***	***
Landed value	***	***
Injury margin	***	***
Injury margin %	***	***
Injury margin % Range	10-20	10-20

Conclusions

105. After examining the issues raised and the submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, the Authority concludes that:
- The subject goods have entered the Indian market from the subject country below associated normal values, thus resulting in dumping of the subject goods;
 - The dumping margins of the subject goods imported from the subject country is above de-minimis;
 - The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods; and
 - The material injury to the domestic industry has been caused due to dumped imports of the subject goods from the subject country.

Indian industry's interest & other issues:

106. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is

in the general interest of the country. Imposition of anti dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

107. With regard to the contention of Solar Industries India on adverse effect of imports on the consumer industry, the authority notes that no verifiable information has been provided to establish significant adverse effect of the proposed duty on user industry. It is also noted that imports for exports have been exempted by Government of India without payment of anti dumping duty under Duty Exemption Scheme, and therefore proposed anti dumping duty shall not impact these imports.

Recommendation

108. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information, *inter alia*, on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted a detailed investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the anti-dumping rules and having established positive dumping margins as well as injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive duty is required to offset dumping of subject goods into India and consequent injury caused to domestic industry. Taking into account the factual matrix of the case and submissions made by various interested parties, it is considered appropriate to recommend anti dumping duty by way of fixed quantum basis in US \$. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.
109. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty as per amount specified in Col 9 of the table below is recommended to be imposed from the date of this notification in the event of acceptance of these recommendations by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Table

S N	Hea ding s	Description of goods	Specific ation	Countr y of origin	Countr y of export	Prod ucer	Export er	Amou nt	Unit of mea sure men t	Cur renc y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	282 990 10	Sodium Perchlorate	All Grades	People 's Republ ic of China	Any	Any	Any	0.23	Kg	US\$
2	282 990 10	Sodium Perchlorate	All Grades	Any	People' s Republ ic of China	Any	Any	0.23	Kg	US\$

110. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
111. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

J. S. DEEPAK, Designated Authority